04 - न्यायपालिका संदिग्ध न बने

05 - साथी को चुनना और साथ रहना संवैधानिक अधिकार

A Daily News Magazine
भोपाल
सोमवार, 6 अप्रैल, 2026

06 - 'संकट मोचन समारोह' में आज से बहेगी संगीत की गंगा

07 - उपार्जन से पहले गोदामों में गेहूं भंडारण के सत्यापन...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 213, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

तमिलनाडु विस चुनाव : क्यों बन सकती है त्रिशंकु विधानसभा

आर राजागोपालन

तमिलनाडु में चुनाव प्रचार तेज़ हो गया है। 23 अप्रैल को मतदान होगा और 234 सीटों वाली विधानसभा के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। 2026 के नतीजे एक नया राजनीतिक सरप्राइज और अप्रत्याशित मोड़ ला सकते हैं। लगभग 6 करोड़ वोटर नए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। 21 राजनीतिक पार्टियों ने करीब 2,200 उम्मीदवार उतारे हैं। कई तरह के समीकरण, नया जनादेश और नए चेहरे 5 मई से अगले पांच साल के लिए विधायक बनेंगे।

पिछले 70 साल से राज्य में बारी-बारी से डीएमके या एआईएडीएमके की सरकार बनती रही है। 2026 के चुनाव में पहली बार डीएमके 234 में से 164 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एआईएडीएमके ने 167 उम्मीदवार उतारे हैं। क्या यह सहयोगियों को ज्यादा सीट देने का संकेत है, या फिर उनके प्रभाव में कमजोरी दिखाता है?

दोनों द्रविड़ पार्टियों के गठबंधन में एक-एक राष्ट्रीय पार्टी शामिल है। दोनों ने अपनी नजर में 'कमजोर' सीटें सहयोगियों को दी हैं–डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीटें दी हैं, जबकि एआईएडीएमके ने बीजेपी को 27 सीटें दी हैं। इससे भी त्रिशंकु विधानसभा की संभावना का संकेत मिलता है।

डीएमके-कांग्रेस गठबंधन में राहुल गांधी अलग-थलग नज़र आ रहे हैं। अंदर से वह विजय की टीवीके के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन विजय अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी रैलियों में बहुत बड़ी भीड़ जुटती है। तमिलनाडु में लगभग हर पार्टी सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी विवाद और विरोध का सामना कर रही है। वीसीके के संस्थापक-अध्यक्ष थोल तिरुमावलवन ने कहा कि अगर डीएमके को बहुमत भी मिल जाता है, तब भी बीजेपी उसे तोड़ने की कोशिश कर सकती है। इस बयान से सहयोगी दलों में चिंता बढ़ गई है। डीएमके को सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ रहा है। एमके स्टालिन छह दलों वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA) का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कई सहयोगी डीएमके द्वारा कांग्रेस को 28 और प्रेमलता की DMDK को 10 सीटें देने से नाराज हैं। वीसीके, एमडीएमके और दो वामपंथी दलों में भी नाराज़गी है क्योंकि राज्यसभा सीटें कांग्रेस और डीएमडीके को दी गईं। प्रेमलता की डीएमडीके की अचानक एंट्री से रिश्तों में और तनाव बढ़ गया है।

कांग्रेस में भी असंतोष दिख रहा है. विरुधुनगर से सांसद मणिक्कम टैगोर ने तमिलनाडु के लिए कांग्रेस चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भेजा। करूर से सांसद एस जोथिमणि ने सार्वजनिक रूप से नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा कि असली कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम 'बेचे जा रहे हैं। बीजेपी में भी अंदरूनी समस्याएं हैं। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सीट बंटवारे को लेकर चुनाव लड़ने से पीछे हटने की बात कही थी, कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें टिकट नहीं मिला। राज्य इकाई ने पीयूष गोयल से उन्हें मनाने को कहा। अब लगता है कि समझौता हो गया है और अन्नामलाई केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को मानने के लिए तैयार हो गए हैं।

एआईएडीएमके, विजय की टीवीके और सीमैन की एनटीके की रैलियों में बहुत बड़ी भीड़ जुट रही है। डीएमके नेताओं को मिला-जुला समर्थन मिल रहा है और एमके स्टालिन को सबसे ज्यादा सत्ता विरोधी माहौल का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव का एक बड़ा मुद्दा ड्रग्स का खतरा है। तमिल न्यूज चैनल, जो पहले डीएमके की तारीफ करते थे, अब सभी पार्टियों को ज्यादा बराबरी से कवर कर रहे हैं। फर्ज़ी एआई से बने वीडियो भी भ्रम पैदा कर रहे हैं।

डीएमके और एआईएडीएमके की तमिलनाडु के हर गांव में मजबूत पकड़ है.।बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की जमीनी मौजूदगी इतनी मजबूत नहीं है। तमिल सिनेमा के 'सुपरहीरो' जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई पार्टी टीवीके (तमिल वेत्री कझगम) के चुनाव मैदान में आने से पहली बार तमिलनाडु में चार तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है।

विजय की एंट्री से राज्य में ईसाई समुदाय को रणनीतिक फायदा मिल सकता है। अल्पसंख्यक वोट बैंक अब दोधारी तलवार बन गया है। पहली बार इन वोटों का कुछ हिस्सा डीएमके से टीवीके की ओर जा सकता है। 1990 के दशक से विजय के करीब 5 हजार फैन क्लब हैं।

नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के कारण तमिलनाडु में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, जिसका फायदा एआईएडीएमके नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी को हो सकता है। जयललिता के समय एआईएडीएमके के घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा भी था। जयललिता को दक्षिणपंथी सोच के करीब माना जाता था और उन्होंने मोदी के गुजरात मुख्यमंत्री बनने पर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। बीजेपी के कमल चिन्ह की तमिलनाडु में कुछ पहचान है और पिछली विधानसभा में उसके चार विधायक थे।

कांग्रेस एक राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी बनी हुई है। डीएमके के साथ उसका गठबंधन धर्मनिरपेक्ष वोटों को मजबूत करता है। राहुल गांधी ने जनवरी में विजय की फिल्म 'जना नायकन' में देरी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे 'तमिल संस्कृति पर हमला' बताया। इससे कांग्रेस और टीवीके के करीब आने की चर्चा हुई। डीएमके ने सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान इस बड़े बदलाव को रोक लिया।

सीमैन की 'नाम तमिलर काची' (एनटीके) अकेले चुनाव लड़ रही है। उसका लगभग 8 प्रतिशत वोट शेयर माना जाता है, जो तमिल राष्ट्रवाद के समर्थकों और LTTE नेता प्रभाकरण व तमिल ईलम समर्थकों से आता है। डीएमके के चुनावी भाषणों में बीजेपी और मोदी-अमित शाह पर ज्यादा हमला किया जा रहा है। डीएमके की रणनीति अल्पसंख्यक वोटों को मजबूत करने की है, लेकिन विजय ईसाई और मुस्लिम वोट अपनी ओर खींच सकते हैं।

चुनाव में फंडिंग और देर रात पैसे बांटने जैसे बाहरी फैक्टर भी असर डाल रहे हैं। पहली बार 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन द्वारा कई पार्टियों को फंड देने की खबर है। चुनावी घोषणा पत्र अब 'मज़ाक' बनते जा रहे हैं, जिनमें फ्री फ्रिज, लैपटॉप, ग्राइंडर, व्हीलचेयर, छात्रों के लिए वाईफाई और पुराने घरेलू सामान बदलने के लिए 8 हजार रुपये का कूपन जैसे वादे किए जा रहे हैं। पार्टियां फ्री सुविधाओं के मामले में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने कहा कि 517 वादों में से 63 वादे 2021 के चुनाव से ही दोबारा नए नाम से लाए गए हैं।

चुनाव में जाति समीकरण भी अहम भूमिका निभाएंगे। अल्पसंख्यक वोट बंटने की स्थिति में कोनार, मुक्कुलथोर, मुथरैयार और अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कई सीटों पर जीत का अंतर एक हजार से भी कम रह सकता है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

बंगाल में टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है

पीएम बोले-चुनाव के बाद चुन-चुनकर हिसाब करेंगे

कोलकाता (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में चुनावी सभा में कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, घुसपैठ और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ने जनता को भय और असुरक्षा के माहौल में धकेल दिया है। पीएम मोदी ने कहा- टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है और अब जनता बदलाव चाहती है। चुनाव के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चुन-चुनकर हिसाब लिया जाएगा और जनता का लूटा हुआ पैसा वापस कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने संदेशखाली जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बताया। एक ओर टीएमसी के करप्शन का भय है तो दूसरी तरफ विकास को रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है।

मोदी बोले-ये लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुष्टिकरण के इस खेल में बंगाल की महान पहचान को बदला जा रहा है। अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। सोचिए कि कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं कि इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किसलिए हुआ था। यहां हिंदुओं का रहना मुश्किल होगा।

मुझे चुनाव आयोग पर विश्वास, निष्पक्ष चुनाव होंगे

मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव आपके बच्चों का भविष्य तय करने वाला है। इसलिए आप बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। आप अपना वोट अपने परिवार के लिए दीजिए। बीजेपी को वोट देकर परिवर्तन पर मुहर लगाइए। मुझे चुनाव आयोग पर विश्वास है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा। तृणमूल के शासन काल में बंगाल की डेमोक्रेसी में भयंकर बदलाव आया है। इन घुसपैठियों को सीधा टीएमसी का समर्थन मिलता है। इसलिए भारत सरकार घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें बाहर निकालने का काम कर रही है। दुनिया के बड़े-बड़े देश अपने देश घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन बंगाल में घुसपैठियों की बचाने की कोशिश होती है। इसलिए टीएमसी सरकार एसआईआर का विरोध करती है। टीएमसी के अन्याय की लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन अब यह विकास का केंद्र बनेगा।

36 घंटे में दुश्मन के बीच से पायलट को सुरक्षित निकाला

ईरान में सफल रहा अमरीका का 'मिशन पायलट' अभियान

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के एक एफ-15 फाइटर जेट को ईरान के ऊपर मार गिराए जाने के 36 घंटे बाद उसके दोनों पायलट को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बचा लिया है। शनिवार को स्पेशल कमांडो यूनिट ने दर्जनों लड़ाकू विमानों के साथ ईरान में ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरानी फोर्स को उस इलाके तक पहुंचने से रोकने के लिए हमले भी किए। इस दौरान भारी गोलीबारी हुई, लेकिन अंत में अमेरिकी टीम पायलट को सुरक्षित निकालने में सफल रही और सभी सैनिक ईरान से बाहर आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करार दिया है। **पैराशूट से उतरने के बाद घायल हुआ था अफसर-** अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने 3 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान ने शुक्रवार को एफ-15 विमान गिरा दिया था। उसमें दो लोग थे। एक मेन पायलट और एक एयरमैन यानी वेपन सिस्टम ऑफीसर (जो हथियारों को ऑपरेट करता है)।

सीआईए ने अफवाह फैलाकर ईरान को भटकाया

अमेरिका और ईरान एयरमैन को ढूंढ रहे थे। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड भी उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंच गई थी। एयरमैन को ढूंढ़ना बहुत मुश्किल था। इसके लिए सीआईए ने एक चाल चली। उन्होंने ईरान के अंदर गलत जानकारी फैलाई कि अमेरिकी सेना उसे पहले ही ढूंढ़ चुकी है और उसे निकालने की तैयारी कर रही है। इससे ईरान की खोज की दिशा भटक गई।

शरद की सुबह

जब प्रत्येक पौधा
जहां भी वह उगा है
और जहां तक
धंसी हुई है उसकी जड़ें
वह जमीन उसकी अपनी होगी
उसकी अपनी ठसक होगी
हर शाख की
अपनी लचक होगी

हरेक फूल का
अपना रंग होगा
जिस पर रिझेंगी तितलियां
और कलियों को देख
झूम उठेगा भौरा
उसकी आज़ाद खयाली का
ध्यान रख हवा भी देगी
उसे और हवा

उसे उसकी स्वतंत्रता के
छद्म होने का
बोध नहीं होगा
और गंध उड़ा ले जाएगी
दूर–दूर तक उसकी कीर्ति

यकीन मानिए जब ऐसा होगा
तब सचमुच वसंत होगा
इस पृथ्वी पर
वसंत होगा, नागरिकों का
मौलिक अधिकार
और संविधान का मूल भाव

फिलहाल ऐसा वसंत
कहीं है...?
इस पृथ्वी पर...!

– अरुण सातले

सघन रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण, हादसे की होगी निष्पक्ष जांच

राज्य सरकार प्रभावित परिजन के साथ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल कोतमा, अनूपपुर में हुए दुखद हादसे में काल-कवलित नागरिकों के परिजन को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 4-4 लाख, संबल योजना के अंतर्गत 4-4 लाख और रेडक्रॉस से 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 2-2 लाख रुपये और रेडक्रॉस से 50-50 हजार रुपये राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिवंगतों की आत्मा को शांति और परिजन को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिजन के साथ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अनूपपुर जिले के कोतमा क्षेत्र में एक लॉज भवन ध्वस्त होने की दुखद घटना के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया था कि राहत एवं बचाव कार्यों में कोई कमी न रहे और प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाए। उल्लेखनीय है कि इस दुखद घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए थे। घायलों में से गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को बेहतर उपचार के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। अन्य घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में जारी है। शनिवार शाम से प्रारंभ हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन आज रविवार दोपहर तक जारी रहा। रेस्क्यू कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, प्रशासन तथा एसईसीएल की टीमों ने आधुनिक मशीनों एवं डॉग स्क्वॉड की मदद से मलबे के एक-एक हिस्से की गहन तलाशी ली। रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालकर तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जबकि 3 अन्य व्यक्तियों के शव बरामद किए गए। मृतकों की पहचान हनुमान दीन यादव, रामकृपाल यादव और एक अन्य स्थानीय निवासी के रूप में हुई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप अहिरवार और कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री दिलीप जायसवाल पूरी रात घटनास्थल पर उपस्थित रहकर राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व करते रहे। प्रभारी मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने बताया कि इस गंभीर हादसे की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसईसीएल की टीमों, पुलिस बल एवं सहयोग करने वाले स्थानीय नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

दिल्ली में सरकारी दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़

पुलिस ने जब्त किया 70 लाख रुपए का अवैध स्टॉक

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वितरण के लिए रखी गई सरकारी दवाओं की हेराफेरी और बिक्री में शामिल एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया और लगभग 70 लाख रुपए की दवाएं और परिवहन में इस्तेमाल किए गए दो गाड़ियां बरामद किए। पुलिस के अनुसार, यह ऑपरेशन क्राइम ब्रांच की एनआर-।। टीम की ओर से एसीपी गिरीश कौशिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर नीरज शर्मा के नेतृत्व में सब-इंस्पेक्टर प्रीतम चंद की ओर से जुटाई गई विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर किया गया था। आरोपियों की पहचान 53 वर्षीय नीरज कुमार, 47 वर्षीय सुशील कुमार के तौर पर हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के रहने वाले हैं। वहीं 48 वर्षीय एक अन्य आरोपी लक्ष्मण मुखिया दिल्ली का रहने वाला है। इन्हें 2 अप्रैल को तीस हजारी के राजेंद्र बाजार के पास महिंद्रा चैंपियन टेम्पो और बलेनो कार में दवाओं की एक बड़ी खेप ले जाते समय पकड़ा गया था।

रैकेट में कौन-कौन था शामिल, पुलिस ने सब बताया

एक अधिकारी ने बताया कि बरामद की गई सभी दवाएं और वाहन मामले की संपत्ति के रूप में जब्त कर लिए गए हैं और कानून के अनुसार क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस रैकेट में अस्पताल के कर्मचारियों, ट्रांसपोर्टरों और वितरकों से बनी एक सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला शामिल थी, जिसके माध्यम से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में वितरित की जाने वाली दवाओं को डायवर्ट किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि अन्य सहयोगियों की पहचान करने, वित्तीय लेनदेन का पता लगाने और नेटवर्क के संपूर्ण तौर-तरीकों को उजागर करने के प्रयास जारी हैं।

हम कोलकाता तक पहुंचेंगे और उनको घर में घुसकर मारेंगे

● पाकिस्तान की भारत को धमकी-अगला संघर्ष सीमा तक नहीं रहेगा

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन (छिपकर हमला) करता है, तो इस बार संघर्ष सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि भारत अपने लोगों या हिरासत में बंद पाकिस्तानियों का इस्तेमाल करके झूठा ड्रामा रचने की योजना बना रहा है। पिछले साल की तरह इस बार भारत को और ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आसिफ ने आगे ये भी कहा कि शवों को कहीं रखकर पाकिस्तान पर आतंकवाद का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने (भारत ने) इस दावे के लिए कोई सबूत नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरलम में एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी थी।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 6 अप्रैल 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

स्कूल बसों का लंदन जैसा हाईटेक नेटवर्क तेलंगाना में

- एक रूट के कई स्कूलों के लिए साझा बस, खास एप से जुड़ेंगे पेरेंट्स, स्कूल-ऑपरेटर

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का हाईटेक इलाका 'साइबराबाद' अब बड़े बदलाव की दहलीज पर है। अक्सर ट्रैफिक जाम व स्कूल छोड़ते वक्त होने वाली अफरा-तफरी से जूझने वाले इस क्षेत्र के लिए साइबराबाद पुलिस और 'सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल' (एससीएससी) ने 'लंदन ट्रांसपोर्ट मॉडल' से प्रेरित मास्टरप्लान तैयार किया है। नए 'स्टूडेंट मोबिलिटी सिस्टम' का मकसद जाम खत्म करना, बच्चों की सुरक्षा

को अभेद्य बनाना, माता-पिता का तनाव घटाने के साथ स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के मौके भी पैदा करना भी है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर डॉ. एम. रमेश बताते हैं, 'हाईटेक सिटी और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा स्कूल जाने वाले बच्चों और उन्हें छोड़ने जाने वाले निजी वाहनों का होता है। क्षेत्र के अधिकांश स्कूल अपनी बस सेवा नहीं देते। इस वजह से पेरेंट्स निजी वाहनों से बच्चों को छोड़ते हैं, ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है।' डॉ. रमेश ने कहा, पुलिस खास एप विकसित कर रही है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिभावकों, स्कूलों और बस ऑपरेटरों को एक सूत्र में पिरोएगा। हालांकि इस 'गेम-चेंजर' एप का नाम अभी तय होना बाकी है, क्योंकि अधिकारी सभी हितधारकों की राय लेकर प्रभावी नाम रखना चाहते हैं।

अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों ने पीएम को लिखा पत्र

- ब्लैक बॉक्स डेटा जारी करने की मांग, 260 लोगों की हुई थी मौत

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया विमान हादसे को 10 महीने हो गए हैं। अब पीड़ितों के परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर 'कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर' (सीवीआर) और 'ब्लैक बॉक्स' का डेटा जारी करने का आग्रह किया है। बता दें कि इस हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी। एअर इंडिया की उड़ान एआई 171 (बोइंग 787-8 का

विमान) लंदन जाने वाली थी लेकिन यह विमान 12 जून, 2025 को सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ क्षण बाद ही एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आग लग गई जिससे उसमें सवार 242 लोगों में से 241 व्यक्तियों समेत जमीन पर मौजूद 19 लोगों की मौत हो गई। गुजरात भर से लगभग 30 शोक संतप्त परिवार शनिवार को अहमदाबाद में एकत्रित हुए और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस त्रासदी के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए सीवीआर और 'ब्लैक बॉक्स' (फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर) का डेटा जारी करने का अनुरोध किया।

12 हजार करोड़ की लागत, ढाई घंटे में पूरा होगा सफर

पीएम मोदी जल्द देने वाले हैं दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह एक्सप्रेसवे उत्तर भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे जाएगा। इससे इस रूट पर आने-जाने वालों को तेज और ज्यादा बेहतर विकल्प मिलेगा। 210 किलोमीटर का यह कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के चालू होने से दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर भीड़ कम होने की उम्मीद है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर का है। इस एक्सप्रेसवे के

शुरू होने के बाद यात्रा का समय कम होगा। अभी दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय लगभग 6.5 घंटे है। एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद यात्रा का समय सिर्फ 2.5 घंटे हो जाएगा। इससे टूरिस्टों को भी सबसे अधिक फायदा होगा। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे छह-लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर है। इस पर कारों के लिए तय स्पीड लिमिट 100 किमी प्रतिघंटा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होता है और देहरादून पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर से गुजरता है। तेज रफ़्तार और बिना रुकावट के सफर के लिए बनाए गए इस एक्सप्रेसवे में सात इंटरचेंज, दो रेल ओवरब्रिज, 10 बड़े पुल और 14 रास्ते के किनारे की सुविधाएं हैं। इनका मकसद यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाना है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की एक बड़ी खासियत राजाजी नेशनल पार्क से गुजरने वाला 12 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन है। इसे जंगली जानवरों के लिए डिजाइन किया गया है।

देश में अब नहीं होगी खाद की कोई कमी!

20 देशों से हो रहा है इंतजाम, युद्ध स्तर पर शुरू हुआ काम

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर दुनियाभर के देशों में नजर आ रहा। ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल के युद्ध की वजह से कच्चे तेल और गैस के संकट से कई देश जूझ रहे, वहीं फर्टिलाइजर सप्लाई पर भी इसका साफ असर नजर आ रहा। इस जंग के कारण दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स की सप्लाई टाइट हो गई है। इससे भारत की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। यह संकट ऐसे

समय आया है जब देश में खरीफ की बुवाई का सीजन अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाला है। ऐसे में उर्वरक आपूर्ति बाधित होने के मद्देनजर भारत ने नाइट्रोजन और फॉस्फेट आधारित फर्टिलाइजर्स को लेकर खास रणनीति अपनाई है। इसके लिए प्रमुख उत्पादकों और निर्यातकों के साथ वैकल्पिक स्रोत सुरक्षित करने के लिए बातचीत की जा रही है।

रूस ने दिया है पीएम मोदी को आश्वासन

उधर, रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने गुरुवार को नई दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फर्टिलाइजर्स के संबंध में अहम जानकारी दी। मंतुरोव ने बताया कि मॉस्को ने दिसंबर 2025 से भारत को खनिज उर्वरकों की आपूर्ति में 40 फीसदी की वृद्धि की है। उन्होंने मोदी को आश्वासन दिया कि रूस भारत की बढ़ती उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर है। दोनों पक्षों ने भारत-रूस फर्टिलाइजर्स निर्माण संयुक्त उद्यम की स्थापना में हुई प्रगति पर भी चर्चा की।

खाद आपूर्ति को लेकर ऐक्टिव भारतीय दूतावास

इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि खाद आपूर्ति को लेकर लगभग 20 देशों में भारतीय दूतावास युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। वो स्थानीय फर्टिलाइजर कंपनियों के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि आवश्यक आपूर्ति की व्यवस्था की जा सके। सूत्रों के मुताबिक, भारत ने चावल, सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, अल्जीरिया और मिस्र से संपर्क किया है।

एलपीजी के मोर्चे पर फिर से मिली बड़ी खुशखबरी!

- ग्रीन आशा ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अब तक निकल चुके हैं 9 शिप

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा। ऐसे में कई देश एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हालांकि, एलपीजी के मोर्चे पर देश के लिए खुशखबरी है। भारतीय ध्वज वाले जहाज ग्रीन आशा ने ईरान के पास मौजूद संकरे समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव शुरू होने के बाद, यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने वाला भारत का नौवां जहाज है। ईरान ने अमेरिका, इजरायल से युद्ध शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। इसको दुनिया के एनर्जी सेक्टर के लिए काफी अहम रास्ता माना जाता है।

अब तक ये भारतीय शिप कर चुके हैं होर्मुज पार

भारतीय ध्वज वाले जहाज ग्रीन आशा ने ईरान के पास मौजूद होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। ग्रीन आशा की यात्रा से पहले, कम से कम आठ भारतीय जहाज इस रूट से गुजर चुके हैं। इनमें एलपीजी ले जाने वाले बीडब्ल्यू टीवाईआर और बीडब्ल्यू ईएलएम शामिल थे। जिन्होंने इस संघर्ष क्षेत्र से लगभग 94,000 टन माल का परिवहन किया।

खाद फैक्ट्री से रासायनिक कचरे का रिसाव

बड़वानी के गांव में निकल रहा जहरीला पानी, एक्शन में प्रशासन

बड़वानी (नप्र)। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पानसेमल क्षेत्र की वलजिरी पंचायत इन दिनों गंभीर जल संकट और रासायनिक प्रदूषण की चपेट में है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि ग्रामीणों के अनुसार अब नलों और बोरवेल से पानी नहीं, बल्कि केमिकल मिला जहरीला पानी निकल रहा है। केमिकल के कारण लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। टाकली गांव के ग्रामीणों का कहना है कि कई कुएं और बोरवेल पूरी तरह से दूषित हो चुके हैं। इस जहरीले पानी से फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं लोगों के सामने पीने के पानी का भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मजबूरी में ग्रामीणों को दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

खाद फैक्ट्री से हो रहा है रिसाव- मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। जिला पंचायत

सीईओ काजल जावला के निर्देश पर पीएचई विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले संकेत मिले हैं कि पास की एक खाद फैक्ट्री से रासायनिक कचरे का रिसाव हो रहा है, जो जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है।ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन का एक्शन हुआ।

क्यों बने ऐसे हालात- ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। उधर फर्टिलाइजर फैक्ट्री के मालिक रविंद्र चौधरी ने कहा कि वह यथाशीघ्र केमिकल वेस्ट को हटा लेगा। उसमें बताया कि कृषि विभाग ने इस कचरे को नहीं उठाने दिया , इसलिए यह हालात बन गए।

सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया लैब

पीएचई के अधिकारियों ने पानी के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन शुरुआती निष्कर्षों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पानसेमल एसडीएम रमेश सिसोदिया ने बताया कि इस तरह की शिकायतें पहले भी मिल चुकी हैं। उस समय फैक्ट्री संचालकों को चेतावनी दी गई थी और उनके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किया गया था। अब एक बार फिर मामला सामने आने पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। रमेश सिसोदिया, एसडीएम, पानसेमल ने कहा कि दूषित पानी को लेकर पहले भी ऐसी कई शिकायतें मिली थीं। जिसके बाद फैक्ट्री संचालक को चेतावनी दी गई है। मामले में केस दर्ज हुआ है। सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मिट्टी में मिले माफिया से कम नहीं था सालार मसूद

- सीएम योगी बोले-महाराजा सुहेलदेव ने मसूद को जहन्नुम में भेजा

लखनऊ (एजेंसी)। भारतेंदु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संवेदनशील सरकार ही संकट के समय जनता की रक्षा करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में राजनीतिक कारणों से कई महान नायकों को भुला दिया गया, लेकिन अब उन्हें सम्मान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। योगी ने महाराजा सुहेलदेव के शौर्य का उल्लेख करते हुए कहा कि एक हजार वर्ष पूर्व उन्होंने विदेशी आक्रांता सालार मसूद को परास्त कर देश और समाज की रक्षा की थी। उसे मिट्टी में मिला दिया था। पहले जिस स्थान पर सालार मसूद के नाम पर मेले लगते थे, वहीं अब सुहेलदेवजी के स्मारक पर लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं।

चुनावी रेवड़ियों से राज्यों पर बढ़ता जा रहा कर्ज

लाड़ली बहना के कारण एमपी का कर्ज रेड लाइन में

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव में फ्री राशन, महिलाओं को नकदी जैसी 'मुफ्त की रेवड़ियों' वाली योजनाएं राज्यों के लिए बड़ा बोझ बन रही हैं। हालत यह है कि इनको पूरा करने के लिए राज्य न पर्याप्त संसाधन जुटा पा रहे हैं और न संतुलित बजट बना पा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो इन घोषणाओं का बोझ कुल राजस्व प्राप्तियों के 30 से 40 फीसदी तक पहुंच गया है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में नकदी संकट की विकट स्थिति है। राज्य में सीएम, मंत्री, विधायकों समेत अफसरों के वेतन-पेंशन टालने पड़े। तेलंगाना को चुनावी

घोषणाओं के लिए हर साल 1 लाख करोड़ चाहिए, पर बजट की कमी से कई योजनाएं अटकी हैं। मप्र में लाड़ली बहना योजना के चलते जीएसडीटी के मुकाबले कर्ज 27 से बढ़कर 32 फीसदी पहुंच गया। महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के दबाव के कारण त्योहारों में मिलने वाली राशन किट योजना बंद कर दी गई है।

ईरान ने अब सी-130 विमान गिराने का किया दावा

- बोला-रेस्क्यू मिशन में शामिल अमेरिकी विमान किया जमींदोज

तेहरान (एजेंसी)। ईरान ने रविवार को दावा किया है कि उसने अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल सी-130 कैटेगरी का एक विमान मार गिराया। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि यह विमान इस्फहान के दक्षिणी इलाके में लापता अमेरिकी एयरमैन की तलाश में लगा हुआ था। यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ देर पहले ही ट्रम्प ने घोषणा की है कि लापता एयरमैन को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचा लिया गया है। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि यह अधिकारी एक कर्नल थे, जो एफ-15ई लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद लापता हो गए थे। ईरान ने ट्रम्प के 48 घंटे में होर्मुज खोलने के अल्टीमेटम को ठुकरा दिया है। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका बेबस और घबराकर धमकियां दे रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ करेगी मामले की सुनवाई

सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री की अब है तैयारी!

नई दिल्ली (एजेंसी)। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से शुरू हुआ विवाद अब एक ऐतिहासिक संवैधानिक मोड़ पर खड़ा है। 7 अप्रैल 2026 से भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ उन व्यापक कानूनी सवालों पर सुनवाई शुरू करने जा रही है। यह न केवल हिंदू धर्म, बल्कि मुस्लिम, पारसी और दाऊदी बोहरा समुदायों की धार्मिक प्रथाओं को भी प्रभावित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह पीठ केवल सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर विचार नहीं कर रही है बल्कि कई मामले शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे कई सवाल

संविधान पीठ कुछ मुद्दों पर स्पष्टता लाने की कोशिश कर सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दायरा और सीमा क्या है। अनुच्छेद 25 (व्यक्तिगत अधिकार) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक संप्रदाय के अधिकार) के बीच तालमेल कैसे बैठेगा। क्या धार्मिक संप्रदाय के अधिकार संविधान के भाग-2 (मौलिक अधिकार) के अधीन हैं। अनुच्छेद 25 और 26 में प्रयुक्त नैतिकता शब्द का अर्थ क्या है। क्या इसमें संवैधानिक नैतिकता शामिल है।

3552 एलपीजी सिलेण्डर जब्त और 10 मामलों में एफआईआर

प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य : खाद्य मंत्री राजपूत

भोपाल (नप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। भारत में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध होने के कारण देश और प्रदेश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही हैं, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। मध्यप्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। मंत्री श्री राजपूत ने अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नही दें तथा घबराहट में खरीदारी (पैनिक बाइंग) से बचें।

पीएनजी कनेक्शन विस्तार पर जोर- सभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाएँ अगले 3 माह में दिये जाने वाले पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित करेंगी। साथ ही सीजीडी संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे आवेदन एवं उसके विरुद्ध दिये जा रहे पीएनजी कनेक्शन की सतत मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सीजीडी संस्थाओं को पीएनजी के लाभ एवं पीएनजी कनेक्शन की प्रक्रिया से संबंधित एफएक्यू तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश नोडल सीजीडी संस्था थिंक गैस को दिये गए हैं। भारत सरकार के गतिशक्ति पोर्टल पर सीजीडी संस्थाओं को पाइप-लाइन अपलोड करने के निर्देश दिये गये। सीजीडी संस्थाएँ जिलेवार एवं लोकेलिटीवाइज कैम्प शेड्यूल कर जिला प्रशासन एवं विभाग को उपलब्ध करायेंगी। शहर के जिन स्थानों में पाइप-लाइन गई है, उसके आस-पास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को ऑयल कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है कि वह पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिये तत्काल आवेदन करें। इसके बाद पीएनजी कनेक्शन प्राप्त नही करने की स्थिति में आगामी 3 माह में एलपीजी का कनेक्शन बंद किया जा सकता है।

जिला आपूर्ति अधिकारियों को एमपीआईडीसी के जिला अधिकारी, जिले में स्थित पॉलीटेक्निक तथा आईटीआई से प्रशिक्षणार्थियों की सूची सीजीडी संस्था को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। सीजीडी संस्था द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों को वर्तमान वेण्डर के साथ क्लब कर मैन पॉवर बढ़ाया जाएगा।

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रदेश में कार्यरत 10 संस्थाओं को पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की मांग और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। पीएनजी पाइप लाइन जिन क्षेत्रों में बिछ चुकी है, वहां आवासीय परिसर, स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज, कम्युनिटी किचन और आंगनवाड़ी केंद्रों को आवेदन प्राप्त होने के 5 दिन में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई

प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2693 स्थानों पर जांच की गई है, जिसमें 3552 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 10 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 666 पेट्रोल पंपों की जांच भी की गई, जिनमें 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। जिला आपूर्ति अधिकारियों और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों को पेट्रोल पंपों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं। घरेलू गैस उपभोक्ताओं द्वारा की गई बुकिंग के अनुरूप सिलेंडरों की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सतत आपूर्ति की जा रही है। उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए गैस बॉटलिंग प्लांट अतिरिक्त समय तक कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित प्लांट और वितरकों के स्टॉक की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारु

प्रदेश में सभी ऑयल कंपनियों के पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पेट्रोल पंपों पर किसी प्रकार की कमी नहीं है और कंपनियों के डिपो से नियमित रूप से आपूर्ति जारी है। बढ़ती मांग को देखते हुए ऑयल कंपनियों के डिपो को भी अधिक समय तक संचालित किया जा रहा है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य बनाए रखा जा सके।

राज्यपाल ने धार के अमर शहीद रवींद्र सिंह राठौर की प्रतिमा का किया अनावरण

शहीद के संघर्ष और बलिदान की गाथा भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा : राज्यपाल श्री पटेल

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने धार जिले के गौरव, अमर शहीद नायब सूबेदार रवींद्र सिंह राठौर की प्रतिमा का रविवार को अनावरण किया। शहीद की वीरता को नमन करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीद की स्मृति को चिरस्थाई बनाने की यह पहल और अटूट निष्ठा अनुकरणीय है।

राज्यपाल द्वारा शहीद की पत्नी श्रीमती प्रताप कंवर और उनके परिवारजन का आत्मीय सम्मान किया गया। नगर परिषद द्वारा बदनावर की माथुर कॉलोनी में नवनिर्मित शहीद पार्क में समारोह का भव्य आयोजन किया गया था।

राज्यपाल श्री पटेल ने शहीद रवींद्र सिंह के जीवन संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्राम पाना के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे रवींद्र सिंह ने सेना में भर्ती होने के लिए लगातार तीन बार प्रयास किए। उनकी यह जिद और देश सेवा का जज्बा ही उन्हें सेना तक ले गया। उन्होने बताया कि 9 जुलाई 2001 को जम्मू की सुरनकोट तहसील के जंगलों में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उनका बलिदान धार जिले सहित पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने परिसर में पौध-रोपण कर पर्यावरण-संरक्षण का संदेश दिया।

समारोह में केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, क्षेत्रीय विधायक श्रीमती नीना वर्मा, पूर्व मंत्री श्री राजवर्धनसिंह दत्तीगांव, नगर परिषद अध्यक्ष मीना शेखर यादव सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

गुरु- शिष्य परंपरा स्कीम के लिए नाट्य संस्थाओं का रिनुअल न होने से कलाकार नाराज

भोपाल। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 मार्च 2026 को जारी परिपत्र में गुरु शिष्य परंपरा स्कीम के तहत देशभर की 1164 सक्रिय संस्थाओं के आवेदन को या तो रिजेक्ट या कूल्ड ऑफ करने कलाकारों में गहरी नाराजी है। इन संस्थाओं में नृत्य संगीत और नाटक तीनों विधाओं की संस्थाएं शामिल हैं। रिजेक्ट और कूल्ड ऑफ की यह कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए की गई है। रिजेक्ट का आशय तो स्पष्ट है। कूल्ड ऑफ से आशय इन संस्थाओं का दो वर्षों के लिए निलंबन है। यह तो हुई देश भर की बात मध्य प्रदेश के फ्रेश और रिन्यूएबल मिलाकर, कुल 78 आवेदन रिजेक्ट और 44 आवेदन कूल्ड ऑफ किए गए हैं। यह जानकारी भोपाल के कलाकारों ने रविवार की दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कलाकारों की मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर है कि अनुदान देने वाली चयन समिति में विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसलिए यह स्थिति बनी।

सभी प्रभावित कलाकार

7 अप्रैल 2026 को दिल्ली प्रस्थान करेंगे और इस विषय पर संस्कार भारती, संस्कृति सचिव एवं माननीय संस्कृति मंत्री से मुलाकात कर इस निर्णय को वापस लिए जाने की मांग करेंगे।

कलाकारों की दूसरी आपत्ति इस बात पर है कि पूर्व के वर्षों में अनुदान का आवेदन करने वाली संस्थाओं के गुरुओं और उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता था। इस प्रक्रिया में अनुदान की पात्रता सिर्फ कागज आधारित न होकर स्वतः भौतिक सत्यापन से जुड़ जाती थी। यह एक उचित तार्किक और पारदर्शी प्रक्रिया थी, जिसका इस बार पालन नहीं किया गया है। कलाकारों का यह भी कहना है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही कुछ संस्थाओं का भौतिक सत्यापन किया गया था। इस सत्यापन में उन संस्थाओं को अनुदान जारी रखने हेतु पात्र माना गया। इसके बावजूद भी उन संस्थाओं का इसी सत्र के लिए रिन्यूवल आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी सत्यापन में जो संस्थाएं अनुदान के लिए योग पाई गई उनका रेनवाल आवेदन ही रिजेक्ट कर दिया गया। कलाकारों का कहना है कि भारत जैसे कला-संस्कृति प्रधान देश में संस्कृति मंत्रालय द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। कलाओं का प्रशिक्षण इस तरह रुक जाने से निकट भविष्य में भारत में कलाओं और कला साधकों का एक विराट शून्य पैदा हो सकता है।

डॉ. संजय गुप्ता बने मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष

एनुअल मीटिंग में बताएंगे रोडमैप, मरीजों का अस्पतालों के प्रति भरोसा बढ़ाने पर रहेगा फोकस

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल एसोसिएशन (एमपीएनएचए) के नए अध्यक्ष के रूप में डॉ. संजय गुप्ता का चयन किया गया है। वे पूर्व अध्यक्ष डॉ. रणधीर सिंह की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। इस अवसर पर रविवार शाम 7 बजे भोपाल के होटल सायाजी में एसोसिएशन की एनुअल मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें नई कार्यकारिणी समिति की घोषणा भी की जाएगी।

डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि बैठक के दौरान वे अपने कार्यकाल का रोडमैप भी पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य फोकस डॉक्टरों, अस्पताल स्टाफ और मरीजों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना रहेगा। उनका मानना है कि जब मरीज और अस्पताल के बीच भरोसा मजबूत होगा, तो इलाज के परिणाम भी बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि मरीजों का विश्वास बढ़ाने के लिए पारदर्शिता और सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। इससे मरीज डॉक्टर की सलाह को गंभीरता से लेंगे और इलाज से जुड़े निर्देशों का पालन बेहतर तरीके से करेंगे। इसका सीधा असर रोग की रोकथाम और उपचार की सफलता पर पड़ेगा।

डॉ. गुप्ता के अनुसार, कई बार संवाद की कमी के कारण अस्पतालों को लेकर नकारात्मक धारणा बनती है। यदि इस अंतर को दूर किया जाए, तो ऐसी स्थितियों में कमी लाई जा सकती है। मीटिंग में एसोसिएशन की आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। इसमें अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार, मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। नई टीम के गठन के साथ ही एमपीएनएचए से उम्मीद की जा रही है कि वह प्रदेश में निजी अस्पतालों की सेवाओं को और मजबूत बनाएगी और मरीजों के हित में ठोस पहल करेगी।

आप पर तीखा हमला, बोले ; राजनीतिक दल नहीं मानते यह लूट करने वाली संस्था

इंदौर शहर में लंबे समय से धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों पर विजयवर्गीय ने जताई नाराजगी

इंदौर। शहर में लंबे समय से धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों को लेकर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। इसी सिलसिले में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में नगर निगम, आईडीए, एमपीईबी, पुलिस विभाग और मेट्रो से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शहर में जारी प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई और आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों की योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में खास तौर पर बड़े गणपति और चंदन नगर चौराहे पर बनने वाले ब्रिज को लेकर चर्चा हुई। मंत्री ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को आगामी सिंहस्थ मेले के लिहाज से बेहद जरूरी बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन ब्रिजों के लिए जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए और बारिश से पहले निर्माण कार्य शुरू करने की पूरी कोशिश की जाए। विजयवर्गीय ने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ तय समय सीमा में काम पूरा करें ताकि शहरवासियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

गणपति ब्रिज निर्माण, तकनीकी रूप से जटिल

मीडिया से बातचीत में कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बड़े गणपति ब्रिज के निर्माण से पहले वहां की यूटिलिटी शिफ्ट करना सबसे बड़ी चुनौती है। यह काम काफी गहराई में होने के कारण तकनीकी रूप से जटिल है इसलिए इसे सावधानी के साथ पूरा करना होगा। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव भी करना पड़ेगा जिसके लिए पुलिस विभाग की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि बरसात को ध्यान में रखते हुए सभी काम समय पर पूरे करने की योजना बनाई गई है।

आप पर तीखा हमला, बोले पार्टी नहीं मानते

वहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह आम आदमी पार्टी को राजनीतिक दल नहीं मानते, बल्कि इसे लूट करने वाली संस्था बताते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर जब तक सब कुछ ठीक चलता है, लोग साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही मतभेद होते हैं लोग अलग होने लगते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी बनने के बाद से कई नेता एक-एक कर उससे अलग होते गए हैं और अब यह कुछ लोगों की निजी कंपनी बनकर रह गई है।

एक-एक प्रोजेक्ट की प्रगति देखी, निर्देश दिए

इसके अलावा चंदन नगर रोड को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि यह शहर की एक महत्वपूर्ण सड़क है और यहां जल्द से जल्द सीसी रोड का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसके लिए अतिक्रमण हटाने और प्रभावित लोगों के शिफ्टिंग जैसे काम पहले पूरे किए जाएंगे ताकि निर्माण में कोई रुकावट न आए। उन्होंने बताया कि चंदन नगर से धार रोड तक बनने वाले ब्रिज को भी मंजूरी मिल चुकी है और इसके टेंडर दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। आने वाले एक से डेढ़ महीने में इस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू होने की उम्मीद है।

आम आदमी पार्टी को राजनीतिक दल नहीं मानते, बल्कि इसे लूट करने वाली संस्था बताते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर जब तक सब कुछ ठीक चलता है, लोग साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही मतभेद होते हैं लोग अलग होने लगते हैं

अब हर महीने प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी

मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन सभी बड़े प्रोजेक्ट्स की हर महीने समीक्षा की जाएगी ताकि काम में देरी न हो और गुणवत्ता भी बनी रहे। उन्होंने कहा कि अलग-अलग विभागों के समन्वय से ही इन कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की, विधानसभा में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. श्री यज्ञदत्त शर्मा की जयंती पर विधानसभा में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका स्मरण किया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, स्व. श्री शर्मा के परिजन, विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. श्री शर्मा ने जनकल्याण के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। स्व. श्री यज्ञदत्त शर्मा, मध्यप्रदेश विधानसभा के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष थे। उन्होंने सदन की गरिमा और लोकतंत्र की मर्यादा को हमेशा बनाए रखा। श्री शर्मा ने अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में सादगी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया।

70 प्रतिशत कला संस्थाओं का अनुदान रोका, कलाकारों में रोष

दिल्ली कूच का ऐलान, बिना कारण रिजेक्ट व कूल्ड ऑफ, पारदर्शिता पर सवाल

भोपाल (नप्र)। संस्कृति मंत्रालय की गुरु-शिष्य परंपरा (रेपर्टरी ग्रांट) योजना में बड़े पैमाने पर अनुदान रोकने के फैसले के खिलाफ अब देशभर के कलाकार एकजुट हो रहे हैं। रविवार को भोपाल में रंगमंच कलाकारों ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि मंत्रालय ने बिना स्पष्ट कारण बताए करीब 70 प्रतिशत से अधिक सक्रिय कला संस्थाओं के आवेदन रिजेक्ट या कूल्ड ऑफ कर दिए हैं। इसे उन्होंने 'अपारदर्शी और भेदभावपूर्ण' निर्णय बताया।

कलाकारों ने ऐलान किया कि 7 अप्रैल को मध्यप्रदेश समेत देशभर के रंगकर्मी दिल्ली पहुंचकर संस्कृति सचिव, संस्कृति मंत्री और संबंधित संगठनों से मुलाकात करेंगे और फैसले पर पुनर्विचार की मांग रखेंगे। बता दें कि देश भर में 1164 संस्थाओं के साथ रिजेक्ट व कूल्ड ऑफ किया गया है।

बढ़ी संख्या में कलाकार प्रभावित- कलाकारों के अनुसार, मध्यप्रदेश में फ्रेश और रिन्युअल मिलाकर 78 आवेदन रिजेक्ट और 44 कूल्ड ऑफ किए गए हैं। पहले जहां प्रदेश में 90 रेपर्टरी सक्रिय थीं, अब यह संख्या घटकर 39 रह गई है। इस फैसले से करीब 650 कलाकार सीधे प्रभावित हुए हैं, जबकि नए अवसर सिर्फ 42 कलाकारों को मिले हैं। कलाकारों का कहना है कि यदि हर कलाकार के परिवार के तीन सदस्य जोड़े जाएं तो करीब 2000 लोगों पर इसका आर्थिक असर पड़ेगा।

इंस्टाग्राम से दोस्ती के बाद छात्रा से रेप

होटल रूम में बंधक बनाकर की थी वारदात, आरोपी फरार

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कजलीखेड़ा थाना इलाके में रहने वाली छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई है। वारदात को इंस्टाग्राम फ्रेंड ने अंजाम दिया है। दोनों बीते तीन महीने से रिलेशन में थे। शनिवार रात को थाने पहुंची पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। लगातार आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। एफआईआर की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया है।

थाना प्रभारी पल्लवी पांडे के मुताबिक 18 वर्षीय युवती स्कूली छात्रा हाल ही में उसने 12 वीं कक्षा का एग्जाम दिया है। जबकि आरोपी आकाश ठाकुर ढाबे पर खाना बनाने का काम करता है। दोनों के बीच इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। पहले फोन पर बातचीत हुई और आरोपी युवक ने उसे मिलने के लिए होटल में बुलाया।

शादी करने का झांसा देकर रेप किया था

जहां उसने शादी करने का झांसा देकर पीड़िता के साथ रेप किया। उसके बाद से वह लगातार पीड़िता का शोषण कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले आरोपी युवक ने शादी करने से इंकार कर दिया और फोन उठाना भी बंद कर दिया। उसकी करतूतों से परेशान होकर थाने पहुंची पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। पुलिस का कहना है जल्द ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 4 माह के शावक की मौत

9 महीने में पांचवीं घटना ; अफसर बोले- दो बाघों के दहाड़ने की आवाज सुनी

नर्मदापुरम (नप्र)। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में एक बार फिर बाघ की मौत का मामला सामने आया है। मटकुली रेंज के नयाखेड़ा क्षेत्र में 4 माह के शावक का शव मिलने से वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीते 9 महीनों में यह बाघों की मौत का पांचवां मामला है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार देर शाम नयाखेड़ा बीट के कक्ष क्रमांक 460 में तैनात फॉरेस्ट गार्ड को दो बाघों की तेज दहाड़ सुनाई दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त की। रात के समय मौके पर एक शावक मृत अवस्था में मिला, जिसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थल की निगरानी की गई।

अफसरों को आपसी संघर्ष के स्पष्ट संकेत मिले- रविवार सुबह अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया, जहां बाघों के आपसी संघर्ष के स्पष्ट संकेत मिले। घटनास्थल के आसपास नर और मादा बाघ के पदचिह्न भी पाए गए, जिससे शावक की मौत किसी अन्य बाघ के हमले में होने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम; सहायक संचालक (पिपरिया एवं पचमढ़ी); तहसीलदार पिपरिया तथा एनटीसीए के प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्धारित एसओपी के अनुसार समस्त आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई। वन विभाग ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया। शव परीक्षण डॉ. गुरुदत्त शर्मा (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व) और डॉ. अमित ओढ़ (रतापानी टाइगर रिजर्व) की टीम ने किया। इसके बाद शावक के शव का अंतिम संस्कार किया गया। फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया कि प्रथम दृष्टया शावक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं और मौत किसी मांसाहारी वन्यजीव के हमले से हुई प्रतीत होती है।

संपादकीय

राघव चड्ढा को हटाने के मायने

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने का मुद्दा राजनीतिक रूप से गर्माता जा रहा है। यूं तो किसी पार्टी द्वारा अपने सदस्य को किसी पद पर रखना या हटाना उसका आंतरिक मामला है, लेकिन आप के इस ताजा घटनाक्रम ने दल के भीतर की कलह को फिर से सामने ला दिया है। आप ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिख कर सदन के उपनेता की जिम्मेदारी अशोक मित्तल को सौंप दी है। इससे यह भी संदेश जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और उनकी समर्थक टोली अपनी सनक और समझ के हिसाब से पार्टी को चला रही है। राघव चड्ढा को हटाने का औपचारिक कारण तो उनका 'पार्टी लाइन' से हटना बताया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी वजह चड्ढा के भाजपा से तार जुड़ने की है। कहा जा रहा है कि चड्ढा महत्वपूर्ण मौकों पर संसद में पार्टी के मुद्दों को उठाने से बचते रहे। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखे हमलों के बजाए उन्होंने समोसे जैसे कम महत्व के मुद्दे उठाए। राघव को पद से हटाकर पार्टी ने एक संदेश देने की कोशिश की है। आप के अनुसार राघव काम्प्रोमाइज्ड हैं। देशहित के मुद्दों पर वो खामोश रहे। आप का यह भी आरोप है कि राघव भाजपा से डरते हैं। बहरहाल, आप के इस फैसले से राघव चड्ढा बेहद नाराज है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आप को चेताया कि ' मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ' ? राघव ने कहा कि मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझना। मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझना। मैं वह नदी हूं जो समय आने पर बाढ़ बन जाती है। समझा जा रहा है कि वह आम आदमी पार्टी के अंदरूनी राज भी खोल सकते हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि वे जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाते रहे हैं। इन्हें उठाने से पार्टी को कैसे नुकसान पहुंच सकता है। उन्हें उपनेता पद से हटाना आप का समन्वित हमला है, जिसका मक़सद संसद में उनकी आवाज़ को दबाना है। नई व्यवस्था के तहत राघव चड्ढा राज्यसभा के सदस्य तो बने रहेंगे, लेकिन उन्हें संसद में बोलने का ज्यादा समय नहीं मिलेगा। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में लंबे वक्त से हैं। वे आप के शुरुआती दिनों से यानी 2012 से पार्टी के साथ हैं। वह केजरीवाल के बेहद क़रीबी रहे हैं। वह कई अहम पदों पर और कोर समूह में रहे हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट चड्ढा पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे। पार्टी को पंजाब में सत्ता में लाने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। जाहिर है कि उनके पास पार्टी के कई राज रहे होंगे। राघव अभी क्या करेंगे, यह देखने की बात है। क्योंकि राज्यसभा में उनका कार्यकाल 2028 तक है। यदि वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। और पार्टी उन्हें नहीं निकालती है तो इसी हालात में उन्हें काम करना होगा। वैसे आम आदमी पार्टी का इतिहास अपनों के लतियाने की घटनाओं से भरा पड़ा है। सबसे पहले पार्टी ने उसके जन्मदाता कारण अण्णा हजारे को ही दरकिनार किया। उसके बाद अण्णा के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल रहे और केजरीवाल के करीबी प्रशांत भूषण, आशुतोष, शाजिया इल्मी, योगेन्द्र यादव, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, स्वाति मालीवाल को ठिकाने लगाया। यानी एक एक कर सभी नेता बाहर कर दिए गए। दरअसल आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल एक असुरक्षा से भरे नेता हैं, जो पार्टी में किसी को भी आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। उनका यही असुरक्षा बोध देश में बहुत कम समय में तेजी से बढ़ती आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए काला टीका साबित हो रहा है। राष्ट्रीय पार्टियां ऐसे नहीं चलतीं।

न्यायपालिका संदिग्ध न बने

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने शालेय शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक में न्यायपालिका के संबंध में जो लेख प्रकाशित किया है उसे लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय व माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय काफी विचलित हुए। सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणियों में उन्होंने एनसीईआरटी की पुस्तक में इस लेख के प्रकाशन पर न केवल आपत्ति की है बल्कि सार्वजनिक रूप से उसे न्यायपालिका के सम्मान पर सुनियोजित हमला माना है। उन्होंने यह भी कहा कि इसे क्षम्य नहीं माना जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बाद सरकार सक्रिय हुई। एनसीईआरटी ने उस लेख को हटाने की घोषणा की और लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। उस माफी का सार्वजनिक प्रकाशन भी हुआ। इसके बावजूद मुख्य न्यायाधीश महोदय संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। स्वाभाविक था कि उनकी भावना व तेवर देखकर भारत सरकार इसका संज्ञान लेती। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में उल्लेख करते हुए कहा कि यह गंभीर घटना है इस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। याने किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहरा कर दंडित किया जाना संभावित तय है।

एनसीईआरटी संसद द्वारा पारित कानून के तहत गठित एक स्वतंत्र इकाई है जिसे देश के शिक्षण संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम तय करने का दायित्व दिया गया है। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम के लिए लेख चुनने हेतु एक कमेटी बनाई थी जिसमें श्री सुमित पंत और श्रीमती सुधा मूर्ति भी शामिल है। सुधा मूर्ति श्री नारायण मूर्ति की पत्नी हैं और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री श्री सुनक की सास है। शायद इसी वजह से उन्हें भारत सरकार ने राज्यसभा में मनोनीत किया है। वैसे भी पाठ्यक्रम निर्धारण समिति के सभी सदस्य परिषद द्वारा नामजद होते हैं और प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से वे सरकार के नामजद जैसे होते हैं। अगर इस समिति ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के विषय को शामिल किया है और यदि यह गलत है तो इसकी जवाबदारी भले ऊपरी तौर पर या सामने से समिति या परिषद की नजर आती हो पर यह जवाबदारी भारत सरकार तक भी जाती है।

हालांकि मैं इस लेख के प्रकाशन में कुछ भी अनुचित या न्यायपालिका के सम्मान को गिराने वाला नहीं मानता। इस लेख में छापा गया है कि न्यायपालिका के जजों के खिलाफ 8600 शिकायत प्राप्त हुई हैं। लगभग 50 लाख प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। कई करोड़ प्रकरण न्यायालयों में विचारार्थ लंबित है। यह संख्या भी तब है जब उच्चतम न्यायालय की पहल पर सरकार ने लोक अदालत का कानून पारित किया है। लाखों सामान्य या छोटे मामले लोक अदालत में हल किये जा रहे हैं। हालांकि लोक अदालत की कार्यवाही को जहां तक मैंने देखा और समझा है वह न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। बिजली, पानी, ट्रैफिक, छोटे-मोटे कर्ज आदि जो विषय लोक अदालत में चिह्नित किए गए हैं वह लोक अदालत के जज साहब के सामने निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक अदालत की तारीख की सार्वजनिक घोषणा की जाती है। बहुत सारे मामलों में तो आपस में विभाग और पक्षकार मिलकर मामला निपटाते हैं। अनेक ऐसे प्रकरण होते हैं जिन्हें पक्षकार लड़ना चाहता है परंतु लंबी-लंबी तारीखों में पेशियों करने अपील दर अपील लड़ते-लड़ते जब न्याय नहीं मिलता तो थक कर समर्पण कर देता है और लोक अदालत के समझौते के नाम पर स्वीकृति देता है।

लंबित प्रकरण निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालयों ने पिछले दिनों चेंबर हियरिंग की प्रथा भी शुरू की जिसमें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वालों या उनके वकीलों को सुने बगैर ही न्यायाधीश फैसला कर देते हैं। फैसला क्या होता है ,बल्कि अधिकांश मामले खारिज कर दिए जाते हैं। ये चेम्बर हियरिंग वस्तुतरू न्यायिक प्रक्रिया को स्वतः न्यायालय द्वारा खंडित करना है, यह एक प्रकार से श्तो हियरिंग्य जैसा है। सामान्य आम आदमी और गरीबों के फैसलों के लिए लोक अदालत हैं लेकिन अमीरों के अरबों खरबों के बैंक चोरी के मामलों के लिए आर्बिट्रेशन सिस्टम है जिसमें सेवानिवृत न्यायाधीश को आर्बिट्रेटर बनाया जाता है। वे पंचायत कर अरबों खरबों के मामले निपटा देते हैं। अगर आर्बिट्रेशन कमेटी के निर्णयों की समीक्षा की जाए तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। सरकारी धन के चोरी या न-अदायगी के जिम्मेदार लोग बड़े आर्थिक और कारावास के दंड से बच जाते हैं।

याचिकाओं के नाम पर प्रतिदिन कई घंटे माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के व्यय होते हैं जिनमें उन पर मार्मिक टिप्पणी होती है परंतु फैसले नहीं होते। पता नहीं अदालतों ने कभी इस पर विचार क्यों नहीं किया। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था और कार्य वितरण के खिलाफ तो कितनी ही बार आवाज उठी है। उच्चतम न्यायालय के ही चार न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफराजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता की थी, जो सारे देश की मीडिया में प्रमुखता से छपी थी। बाद में पत्रकार वार्ता करने वाले न्यायाधीशों में से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। परंतु इतनी बड़ी घटना से माननीय उच्चतम न्यायालय की साख और सम्मान पर चोट नहीं पहुंची। कुछ दिनों पूर्व पुणे के एक लॉ कालेज में बोलते हुए स्वतः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री उज्जवल भुयान ने सरकार के कहने पर हाईकोर्ट जज के ट्रांसफर करने को कालेजियम का गलत निर्णय सार्वजनिक रूप से कहा पर क्या इससे कोर्ट के सम्मान पर चोट नहीं पहुंची? जो पाठ पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था वस्तुतः उसमें न्यायपालिका के खिलाफ कुछ भी नहीं है। केवल वे सूचनाएं दर्ज की गई हैं जिन्हें संसद में एक प्रश्न के उत्तर में भारत के विधिमंत्री ने बताया था। ये सूचनाएं देश के सभी अखबारों व मीडिया में पहले भी आई हैं।

मैं न्यायपालिका का पूरा सम्मान करता हूं। चाहता हूं कि न्यायपालिका की साख सुरक्षित रहे। मैंने लगातार कई कई लेखों में लिखा भी है कि देश की जनता के समक्ष सरकार अविश्वसनीय है, संसद पर भरोसा नहीं, नौकरशाही पर भरोसा नहीं, केवल न्यायपालिका ही विश्वास का आखिरी केंद्र है। यदि न्यायपालिका से विश्वास उठेगा तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। लोग हिंसा की ओर मुड़ेंगे और उसके लिये लाचार होंगे।

हालांकि मैं यह भी मानता हूं कि एक नागरिक के नाते न्यायपालिका की कार्यपद्धति पर चर्चा या टिप्पणी करना एक नागरिक का अधिकार है जिसे दबाना या रोकना लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के अधिकार को सिकोड़ना या सीमित करना होगा। अगर देश के छात्रों को यह मालूम हो जाए कि न्यायपालिका के जजों के खिलाफकितनी शिकायतें लंबित है या कितने प्रकरण सुनवाई के लिए लंबित हैं तो इसमें न्यायपालिका का क्या बिगड़ने वाला है। यह तो और भी अच्छा होता कि लोग न्यायपालिका के प्रति और अधिक सजग होते। शायद प्रत्युत्तर में न्यायपालिका भी अपने दायित्व को और अधिक जिम्मेदारी के साथ पूरा कर पाती या करने के लिए प्रेरित होती।

यह भी सोचना होगा कि पिछले दशकों में कितने ऐसे प्रकरण मीडिया में आए हैं जिनमें माननीय न्यायाधीशों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कई के खिलाफ संसद में महाभियोग भी आया और राजसत्ता तथा न्यायपालिका के मिले-जुले प्रयास से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या फिर संसद और न्यायपालिका दोनों चुप हो गईं। अभी कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के जज माननीय वर्मा के घर रूपयों का ढेर पाया गया। यहां तक की सर्वोच्च न्यायालय की जांच समिति ने भी इसके लिए जज साहब को जिम्मेदार माना। पर अभी तक उनके खिलाफ न कोई कार्रवाई हुई न वह गिरफ्तार हुए न उन्हें जेल में डाला गया। माननीय न्यायाधीश महोदय कल्पना करें कि ऐसी घटना किसी अन्य के साथ होती तो शासन व न्यायपालिका का क्या व्यवहार होता। मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बगैर मैं इतना तो इंगित करना ही चाहता हूं कि श्री लालू प्रसाद यादव, श्री संजय सिंह, श्री हेमंत सोरेन, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री डी राजा, श्री मनीष सिसोदिया और कितने ही ऐसे अन्य नाम लिखे जा सकते हैं जिनके घर से एक रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ परंतु महीनों या सालों न्यायपालिका के आदेश से जेल में रखे गए। माननीय न्यायाधीश के घर से बड़ी संख्या में रुपए प्राप्त हुए। वे स्वस्थ और सकुशल है। इससे न्यायपालिका की साख बढ़ी है या घटी है? इसका फैसला स्वयं न्यायपालिका को करना होगा।

माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की टिप्पणी से पहले देश में शायद ही किसी को पता होगा कि इस किताब के पाठ में क्या छपा है? आज देश के करोड़ों लोगों की जुबान पर उस पाठ की चर्चा है। छिपाने से या हटाने से और अधिक प्रचार होता है। अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी और कार्रवाई के बजाय इसे लोकतांत्रिक तरीके से लिया होता तथा अपनी ओर से एक सूचना जारी करते की उस पाठ्यक्रम में यह भी शामिल कराया जाए कि जो शिकायतें मिली है उनमें कितनों की जांच हुई, कितनी सही या गलत पाई गईं ,जो सही पाई गईं उन पर दोषियों को क्या दंड मिला, इससे न केवल न्यायालय की निष्पक्षता व संवैधानिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होती बल्कि साख भी बढ़ती। मैं अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करूंगा कि वे पाठ्यक्रम को हटाने व दंड देने की भाषा के बजाय इसे सूचना के रूप में देखें व न्यायपालिका की ओर से एक टिप्पणी प्रकाशित करने भेजें। यह शायद उच्चतम न्यायालय की साख को न केवल सुरक्षित रखेगा बल्कि बड़ी ऊंचाई पर ले जाएगा। हाँ इस पाठ का शीर्षक के अवश्य बदला जाना चाहिए, क्योंकि शीर्षक, आक्रमक व गलत संदेश देता है परंतु शायद शीर्ष कोर्ट तो अपनी ही पीठ को हटाना चाहता है एनसीआरटी ने दो सदस्यीय समिति इसके पुनरीक्षण के लिए बनाई पर उसने भी थोड़ा स्वरूप बदलकर वही पाठ छापने को दिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय, इस पर भी आक्रोशित हैं और कुल मिलाकर न्यायपालिका स्वतरूही अपने आपको संदिग्ध बना रही है।

बराबरी की असली कसौटी क्या है?

मुद्दा

सत्य प्रकाश नायक

लेखक जेंडर मुद्दों पर कार्यरत हैं।

रात के ग्यारह बजे एक व्यक्ति बिजली के खंभे पर चढ़ा है। नीचे अँधेरा है और ऊपर करंट का खतरा। तस्वीर के साथ लिखा है कि जिस दिन महिलाएँ भी ऐसे काम करेंगी, उस दिन सच्ची बराबरी होगी। पहली नज़र में यह तर्क सीधा लगता है, लेकिन क्या वास्तव में बराबरी का अर्थ केवल वही काम करना है जो दिखाई देता है। क्या जोखिम ही समानता की अंतिम कसौटी है, या यह सवाल ही अधूरा है।

कभी-कभी हम तस्वीरों से निष्कर्ष निकाल लेते हैं, पर तस्वीरें अक्सर कहानी का आधा हिस्सा ही दिखाती हैं। जो दिखाई देता है, वह श्रम है; जो नहीं दिखाई देता, वह त्याग है। और बराबरी की चर्चा में त्याग का अदृश्य होना ही सबसे बड़ी विडंबना है। इतिहास बताता है कि स्त्रियों को लंबे समय तक शिक्षा, संपत्ति और पेशेवर अवसरों से दूर रखा गया। जब संस्थानों के दरवाज़े बंद थे, तब उनकी अनुपस्थिति को उनकी अक्षमता माना गया। उन्नीसवीं सदी में एक महिला को चिकित्सा शिक्षा पाने के लिए पुरुष की पहचान अपनानी पड़ी, क्योंकि महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश वर्जित था। पहले रास्ते बंद किए गए, फिर पूछा गया कि महिलाएँ दिखती क्यों नहीं। यह बराबरी नहीं थी, यह संरचनात्मक असमानता थी।

भेदभाव अचानक वयस्कता में शुरू नहीं होता। वह बचपन से शुरू होता है। लड़कों को खिलौनों में गाड़ियाँ, औज़ार और बाहर की दुनिया दी जाती है; लड़कियों को रसोई सेट और गुड़िया। लड़कों को चढ़ना, गिरना, जोखिम लेना सिखाया जाता है; लड़कियों को संभलकर चलना और सीमाओं में रहना। धीरे-धीरे यह सामाजिक प्रशिक्षण उनके आत्मविश्वास, आकांक्षाओं और निर्णय लेने की क्षमता को आकार देता है। जब बचपन से ही यह संदेश दिया जाए कि कुछ काम 'तुम्हारे लिए नहीं हैं', तो बड़े होकर अवसरों की असमानता केवल परिणाम होती है, कारण नहीं।

कार्य विभाजन भी तटस्थ नहीं है। समाज ने कामों को 'पुरुष' और 'महिला' श्रेणियों में बाँट दिया। भारी मशीन, निर्माण, तकनीकी मरम्मत पुरुषों के हिस्से में गई। देखभाल, सफाई, खाना बनाना, बच्चों और बुजुर्गों की जिम्मेदारी महिलाओं के हिस्से में। यह बँटवारा जैविक कम और सामाजिक अधिक था। पर समय के साथ इसे प्राकृतिक मान लिया गया। भारतीय समाज में यह असमानता और जटिल हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ से जुड़े आकलनों के अनुसार ग्रामीण भारत में पानी लाने की जिम्मेदारी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं पर है। वे रोज़ कई किलोमीटर पैदल चलती हैं और घंटों कतार में खड़ी रहती हैं। यह श्रम शारीरिक रूप से कठिन है, लेकिन इसे जोखिमपूर्ण कार्यों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह घर के दायरे से जुड़ा है और इसके बदले वेतन नहीं मिलता।

भारत के टाइम यूज़ सर्वे 2019 के अनुसार महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक समय अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्यों में लगाती हैं। ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के विश्लेषण के अनुसार भारतीय महिलाएँ पुरुषों से लगभग आठ गुना अधिक समय देखभाल कार्यों में देती हैं। यदि एक पुरुष प्रतिदिन एक घंटा देता है, तो एक महिला औसतन आठ घंटे देती है। यह केवल समय का अंतर नहीं है; यह अवसर का अंतर है।

जब किसी व्यक्ति का अधिकांश समय अवैतनिक जिम्मेदारियों में व्यतीत होता है, तो वह प्रशिक्षण, कौशल विकास, नेटवर्किंग या जोखिमपूर्ण पेशों में प्रवेश के लिए आवश्यक तैयारी कैसे करेगा।

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अध्ययन से संकेत मिलता है कि यदि घरेलू जिम्मेदारियाँ संतुलित रूप से बाँटी जाएँ, तो महिला श्रम भागीदारी लगभग छह प्रतिशत तक बढ़ सकती है। यह वृद्धि केवल सांख्यिकीय परिवर्तन नहीं होगी; यह लाखों महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग खोलेगी। मैकिंज़ी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि महिलाओं की पूर्ण आर्थिक भागीदारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में खरबों डॉलर की वृद्धि संभव है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व बैंक भी बार-बार इस बात पर बल देते हैं कि देखभाल अर्थव्यवस्था को कमतर आँकना विकास की सबसे बड़ी अदृश्य बाधाओं में से एक है। लेकिन अवसर केवल समय से नहीं रुकते; वे मानसिकता से भी रुकते हैं। अनेक घरों में आज भी लड़कियों की गतिशीलता सीमित की जाती है। देर शाम बाहर रहना, दूर शहर में प्रशिक्षण लेना, फील्ड जॉब करना, जोखिमपूर्ण काम सीखना—इन सब पर प्रश्नचिह्न लगाया जाता है। परिवार की प्रतिष्ठा, सुरक्षा और परंपरा का तर्क दिया जाता है। परिणामस्वरूप लड़कियाँ धीरे-धीरे अपने सपनों को छोटा करना सीख जाती हैं।

लगातार यह सुनना कि तुम नाज़ुक हो, तुम कमजोर

हो, तुम्हें सुरक्षा की ज़रूरत है—केवल बाहरी रोक नहीं है; यह भीतर भी घर कर लेता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर आत्मविश्वास क्षीण होता है। कई महिलाएँ अवसर मिलने पर भी स्वयं को उस भूमिका के योग्य नहीं मानतीं। जब समाज बार-बार सीमाएँ खींचता है, तो व्यक्ति उन सीमाओं को अपनी पहचान का हिस्सा समझने लगता है।

इसी के समानांतर 'मर्दानगी' की एक छवि भी गढ़ी जाती है। कठोर बनो। जोखिम लो। डर मत दिखाओ। कमाओ। घर चलाओ। यह छवि पुरुषों को भावनात्मक अभिव्यक्ति से दूर करती है और महिलाओं को साहसिक भूमिकाओं से। पितृसत्ता केवल महिलाओं को सीमित नहीं करती; वह पुरुषों को भी एक संकीर्ण ढाँचे में बाँध देती है।

फिर एक दिन वही ढाँचा प्रश्न करता है। महिलाएँ कठिन या खतरनाक कामों में कम क्यों दिखती हैं। प्रश्न पूछने वाला यह नहीं देखता कि बचपन से किसे चढ़ना सिखाया गया और किसे रोका गया। किसे जोखिम लेने दिया गया और किसे डर दिखाया गया। किसे देर रात बाहर रहने की छूट मिली और किसे नहीं। किसे कहा गया कि दुनिया तुम्हारी है, और किसे कहा गया कि सीमा पहचानो।

इस संदर्भ में रात ग्यारह बजे खंभे पर क्यों नहीं जैसा प्रश्न अधूरी तस्वीर प्रस्तुत करता है। क्योंकि उसी समय लाखों महिलाएँ घरों में काम कर रही होती हैं। वे भोजन तैयार कर रही होती हैं, बच्चों की देखभाल कर रही होती हैं और अगले दिन की जिम्मेदारियों की तैयारी कर रही होती हैं। यह श्रम बुखार या थकान में भी रुकता नहीं। इसके लिए न वेतन है, न अवकाश, न औपचारिक मान्यता। यह अदृश्य श्रम समाज और अर्थव्यवस्था की बुनियाद है, पर बराबरी की चर्चा में अक्सर इसे स्थान नहीं मिलता।

बराबरी का प्रश्न केवल जोखिमपूर्ण कार्यों में उपस्थिति का नहीं है। असली प्रश्न यह है कि क्या हर व्यक्ति को अपने जीवन का मार्ग चुनने की समान स्वतंत्रता मिली। क्या प्रशिक्षण, सुरक्षा, प्रोत्साहन और अवसर सचमुच समान थे। क्या परिवार और समाज ने समान भरोसा दिया। क्या असफल होने की समान अनुमति दी।

बराबरी का अर्थ यह नहीं कि हर स्त्री खंभे पर चढ़े। बराबरी का अर्थ यह है कि यदि वह चढ़ना चाहे तो कोई उसे रोके नहीं। और यदि वह किसी अन्य भूमिका को चुने तो उसे कमतर न आँका जाए। खंभे पर चढ़ी तस्वीर एक प्रतीक हो सकती है, पर वह अंतिम प्रमाण नहीं है। सच्ची बराबरी तब होगी जब समाज यह स्वीकार करेगा कि घर की रसोई, खेत, दफ्तर और कार्यस्थल—हर जगह किया गया श्रम समान सम्मान का अधिकारी है।

बराबरी की ऊँचाई खंभे से नहीं मापी जाती; वह इस बात से मापी जाती है कि समाज अपने हर सदस्य को कितनी स्वतंत्रता, अवसर और सम्मान देता है। जब प्रश्न पूछने से पहले हम यह जाँचेंगे कि अवसर सचमुच समान थे या नहीं, तब संवाद ईमानदार होगा। और जब स्वतंत्रता वास्तव में साझा होगी, तभी बराबरी का दावा सार्थक होगा।

समरथ को नहीं दोष गुंसाई

कटाक्ष

अतुल चतुर्वेदी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

वे समर्थ हैं इसलिए बीच सड़क पर अपनी चौपहिया खड़ी कर देते हैं। सब अपनी खैर मनाकर इधर उधर से निकल जाते हैं। कोई उनसे पंगा नहीं लेता। वे बाहुबली हैं इसलिए किसी के भी खेत का पानी रोक लेते हैं और उसे अपने खेत में मोड़ लेते हैं कोई उफ़ तक गांव में नहीं करता।

कल ही उन्होंने सुदूर खेत में ज़बरन हमला कर दिया - बहाना यह है कि तुम ऐसा कीटनाशक छिड़क रहे हो जिसके कण हवा के साथ हमारे खेतों में आ रहे हैं और फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। साथ में एक दो पड़ोसी और हम विचार खेत मालिक और ले लिए। घुस गए खेत में। तहस नहस कर दी उसकी खड़ी फसलें पर्यावरण रक्षा और विश्व शांति के नाम पर। यह कैसी विश्व शांति है जो हमेशा जरुरतमंद और छोटे राष्ट्रों के विध्वंस की छाती पर चढ़कर ही आती है और जिस शांति को युद्ध की अदम्य प्यास से स्थापित किया जाता है?

शांति और स्थिरता का यह मॉडल मिसाइलों, ड्रोन पर चढ़कर आता है और अपने स्वार्थ साध कर चला जाता है। फिर नया बहाना, नया लक्ष्य और नई भूख और स्वार्थ का सिलसिला। तुम अपने स्वार्थ और बहाने चुन लो और मैं अपने हित और तरीक़े ढूँढ लेता हूँ। जो समरथ है उसे किस बात का डर? आज समर्थ आदमी न लाइन में लगता है न नियमों की पालना करता है। नियम और कानून लाचार और आम जन के लिए बनाये गए हैं। उसे उसका पालन कर आदर्श नागरिक बनना है। समरथ आदमी को सैंकड़ों काम होते हैं उसे बड़े अधिकारी से मिल अपनी फाइल भी अप्रूव करवानी है और दूसरी जगह जा कर टेंडर भी हथियाना है।

उसे क़ब्ज़ा भी करना है मिडिल मैन बनकर और अगले ही घंटे अहिंसा पर आधारित कार्यक्रम में जाकर गांधी जी के विचारों पर जा कर बोलना भी है। उसे मॉर्निंग वॉक में महिलाओं पर भद्दी सी टिप्पणी भी करनी है और अपना चेहरा उज्ज्वल बनाये रखने के लिए मोहल्ले के व्हाट्स एप ग्रुप में अच्छा सा प्रेरक वचन भी डालना है। समरथ आदमी को हर फटे में पैर देना होता है। उसको निरंतर एक चतुर व्यापारी की तरह अपने हितों की दिशा में सोचते रहना होता है। आजकल सारे समर्थ यही फ़लसफ़ा अपना रहे हैं और विश्व पंचायत नामक संस्था विधवा का विलाप हो गई है। उसका दाना पानी बंद होते देर न लगी यदि ज़्यादा स्यापा किया तो।

बकरियां मैं, मैं कर रही हैं और शेर पूरी बेशर्मी से उन पर आक्रमण कर रहे हैं। बहाना वही सदियों पुराना तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? शेरों ने आपसी सहमति से नया पैंतरा अपना लिया है। तू भी कर गप, मैं भी करूँ गप बाक़ी करेंगे राम नाम जप। विश्व शान्ति के नेपथ्य में जितना चाहो हथियार बेचो और और ऊर्जा के स्त्रोतों पर क़ब्ज़ा जमाओ। मोहल्ले के गुंडों के कौन मुँह लगे? क्या पता कल किस की रसद पानी बंद कर दें ससुरे और किस पर टैरिफ़ की मार लगा दें।

हम तो न तीन में हैं न तेरह में हैं। हम अभी यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस ओर हैं? बल्ली सिंह चीमा के शब्दों में ज्आदमी की ओर हैं या कि आदमखोर हैं?

बड़े दादाओं के औघड़ प्रदर्शन में छुटभैये भौंचक हैं। खिसिया हुआ दुनिया का चौधरी झेंप मिटाने के बहाने ढूँढ रहा है और हम अपना दामन और निष्पक्ष छवि बचाने के चक्कर में बयानों के रूमाल से अपना मुँह साफ़ कर रहे हैं।

समर्थ कब किस से डरे हैं? उनको कब जगत् गति व्यापी है? वे तो अपने स्वार्थों के लिए निर्लज्जता की हद तक जा सकते हैं। कोई भी बहाना ढूँढ आपकी चहारदीवारी लाँघ सकते हैं, कभी भी आपका हुक्का पानी बंद कर सकते हैं। पुलिस भी उनकी है, क़ानून भी उनका गुलाम। शांति के व्याख्याकार भी वही हैं और पैरोकार भी वही। सरदार भी वही हैं और असरदार भी वही। हम तो बस प्यादे हैं जितना वो कहते हैं उतने घर चल देते हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

माया तू झूठी नहीं, झूठ न तेरा रूप...

व्यंग्य

सुधीर देशपांडे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हर काम के लिए वे पैसा लेते थे। जबकि सरकार से उन्हें इसके लिए वेतन भी मिलता था। जब उनसे शिकायत की गई तो बोले 'यह तो जरूरी है।' 'जब पैसा नहीं था, तब भी दुनिया का व्यापार, चलता था लेन देन तब भी होता था। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है।' मैंने कहा तो वे बड़े आत्मविश्वास से बोले-

'देखो भाईसाहब, पैसा ही सब कुछ है। अगर नहीं भी है तो हमने बना दिया है, हमारी नजर में वह बड़ा व्यक्ति है, जिसकी कमाई जबरदस्त है। भले ही वह कमाई कैसे भी आ रही हो। तो तर्क शास्त्र कहता है कि पैसा जो है, वह बड़ा है। इसलिए जिसके पास पैसा है, वह भी बड़ा है। देखो, उसे देखकर, उस हर घर में कोहराम मचा है, जहाँ घर का भला आदमी अपनी महीने भर की तनख्वाह में भी, सुख से घर चला ले रहा है। आप ही सोचिए, अगर पैसा बड़ा न होता तो भला कौन माँ, अपने ढेर पैसा कमाने वाले का बखान, दुनिया भर में करने से चूकती। कौन बाप, अपनी न कमाऊ औलाद को कोसता? पैसा कमाने के नाम पर जिगर के टुकड़े को, परदेस भेजता। और फिर खुद को चुपचाप किसी बड़े से फ्लेट में या कि सड़क पर मरने के लिए छोड़ देता।' 'पर कबीर ..!'- मैंने कहना चाहा।

'यही न कहना चाहते हो कि 'साई इतना दीजिए... ।' देखो पैसा उन्हें भी चाहिए था। तभी तो कपड़ा बुनते थे। पर कबीर मूर्ख थे, जो इतना ही मांगते थे कि जिसमें कुटुंब का पालन पोषण हो जाए और आगंतुक अतिथि का निर्वाह हो जाए। यदि पैसे की तरफ एक बार भी प्यार से देख लिया होता तो वे आज कपड़ा मिलों के मालिक होते। कबीर के कपड़े एक बड़ा ब्रांड होते। परंतु आज वैसा नही है। आज कबीर को सामने रखकर पैसे की अर्थहीन था बताई जा तो रही है पर साधु सन्यासी प्रवचनकार पैसे के बारे में ही सोच रहा है। पिता सोचता है, कुटुंब तो ठीक; सात जन्मों की जुगाड़ हो जाए तो भी कम है।' वे बोलते रहे- 'पैसा है तो सत्ता है, और सत्ता है तो पैसा है। ध्येय पैसा है, लक्ष्य पैसा है। जो यह कहता है कि उसे सत्ता, समाज के कल्याण के लिए चाहिए तो वह साफ तौर पर आपको बेवकूफ बना रहा है। वहाँ सिर्फ पैसा है। पैसा बोले तो सदाचार कम भ्रष्टाचार ज्यादा। सदाचारी कहलाने के शौकीन लोग मौका मिलते ही भ्रष्टाचार में ऐसे कूदते हैं जैसे कि वे इसी मौके की राह देख रहे थे। जिसके पास पैसा आता है, उसके पास नाते, रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, अपरिचित सब ऐसे मंडराने लगते हैं, जैसे फूलों के पास तितलियाँ मंडराती है। गुड़ के पास मक्खियाँ। खाते में पैसों के आने का पता चलते ही सायबर ठग आपके पीछे पड़ जाते हैं। दुश्मनों, ईर्ष्यालुओं, इनकम टेक्स, ईडी को दाल में काला नजर आने लगता है। ये सच है कि पैसा आज की अहम जरूरत है। अंबानी, अडानी, टाटा, गोदरेज, बिड़ला पैसे से पैसा बना रहे हैं। उनके कारखानों में कइयों को रोजगार मिला है। पर राजनेताओं के पास जो पैसा है उसका उपयोग और उससे उत्पन्न रोजगार का पता चले तो बात हो। बाप की कमाई देखकर संतान खुश हैं कि उसे अब कुछ नहीं करना। जब तक यह सब पिता या माता के नाम है तब तक उसकी इज्जत है। दो रोटी का जुगाड़ है। जब यह धन ही नहीं तो कौन पिता कौन माता?'

पर कबीर ने तो ये कहा था-

'कबीर सो धन संचे, जो आगे को होय।'

'सीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देख्यो कोय।।'

तुम अच्छा कबीर के पीछे पड़े हो यार। पैसा है तो सब है। कबीर ने न संचय नहीं किया। कमाल उनके समान ही ताउम्र रहे। पर बाकी के लिए तो पैसा ही महत्त्वपूर्ण रहा न। राजा बदला क्या? सेठ साहूकार बदले क्या? उनकी जायदादें, माल असबाब बढ़ते रहे। ये जरूर था कि जिनके पास कुछ नहीं था, वे कबीर के दोहे पढ पढ़कर गम गलत करते रहे। देखो माया नहीं मरती, मन भी नहीं मरता, बस ये शरीर मरता है। माया अमर है। उसने यहीं रहना है। तो तुम्हारे कबीर ने यह भी कहा है कि शरीर नश्वर है। अनित्य है, पर माया के लिए इस और प्यास बनी रहे।

'माया मुई न मन मुआ, मरि-मरि गया सरीर।'

'आसा तृष्णा नाँ मुई, यौं कहै दास कबीर।।'

पर कबीर यह तो नहीं चाहते थे। आप तो सारा नरेटिव ही बदल रहे हैं। 'इसमें अलग क्या है? यदि नरेटिव बदलने से जब अपने स्वार्थ सध रहे हों तो यह भी जायज है। अब मुझे आज्ञा दें। बैंक का अकाउंट चेक करना है।' उन्होंने कहा और चलते बने।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

साथी को चुनना और साथ रहना संवैधानिक अधिकार

धर्मांतरण विरोधी कानून अंतरधार्मिक विवाहों या सहमति से वयस्क व्यक्तियों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप को प्रतिबंधित नहीं करता। धर्म की परवाह किए बिना, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत संरक्षित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 तथा अधिनियम, 2021 को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अंतरधार्मिक दंपतियों का लिव-इन रिलेशनशिप अपराध है। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय दंपतियों को धर्म के नजरिए से नहीं देखता, बल्कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के रूप में देखता है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश धर्म के गैरकानूनी रूपांतरण निषेध अधिनियम, 2021 अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है और न अंतरधार्मिक दंपतियों को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से रोकता है। यह फैसला अंतरधार्मिक दंपतियों द्वारा दायर 12 याचिकाओं के एक समूह के मामलों में दिया गया। इनमें परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा कथित तौर पर दी गई धमकियों से पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी। यह दिलचस्प था कि इन बारह याचिकाओं में से सात में हिंदू पुरूषों के साथ रहने वाली मुस्लिम महिलाओं के मामले थे। अन्य पांच में मुस्लिम पुरूषों के साथ रहने वाली हिंदू महिलाओं के मामले थे। इन दंपतियों ने अदालत में यह दावा किया कि उनके अंतरधार्मिक संबंधों के कारण उन्हें उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।

सुनवाई के उपरांत उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ अपनी पसंद से रहने का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। किसी व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप करना, दो व्यक्तियों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा। यदि कानून दो व्यक्तियों को, यहां तक कि समान लिंग के व्यक्तियों को भी, शांतिपूर्वक एक साथ रहने की अनुमति देता है, तो कोई भी व्यक्ति परिवार और कोई राज्य ऐसे दो वयस्क व्यक्तियों के विषमलिंगी संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकता है, जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत में लिव-इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है और किसी भी कानून के तहत दंडनीय नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 तथा अधिनियम, 2021 को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अंतरधार्मिक दंपतियों का लिव-इन रिलेशनशिप अपराध है। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय ने दंपतियों को धर्म के नजरिए से नहीं देखता, बल्कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के रूप में देखता है। धर्मांतरण विरोधी कानून के दायरे को स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के लिए, किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध साधनों जैसे कि गलत बयानी, बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव, दबाव, धोखाधड़ी या केवल विवाह के लिए धर्मांतरण द्वारा वास्तविक धर्मांतरण होना आवश्यक है।

न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों का सम्मान धर्म की परवाह किए बिना किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने तर्क दिया था कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले दंपतियों को धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। हालांकि न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायालय मित्र (एमिकस क्यूरी) ने तर्क दिया कि दंपति केवल साथ रह रहे थे। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था। सभी दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने कहा कि किसी भी याचिकाकर्ता ने अपने साथी द्वारा धर्मांतरण के प्रयास का दावा नहीं किया था। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के सिद्धांतों का भी उल्लेख किया और कहा कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो।

राज्य के कर्तव्य की पुष्टि करते हुए, न्यायालय ने अपने फैसले का समापन यह कहते हुए किया कि याचिकाकर्ताओं का अंतरधार्मिक संबंध में रहना मात्र उन्हें भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करता, क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं। जाति, पंथ, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

मूलतः उत्तर प्रदेश धर्म-कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के अनुसार, गलत व्याख्या, बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव, दबाव, प्रलोभन या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या विवाह के माध्यम से किसी धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण निषिद्ध है। यदि आरोपी यह साबित करने में विफल रहता है कि महिला का धर्मांतरण विवाह के उद्देश्य से या बल प्रयोग, प्रलोभन आदि के

द्वारा नहीं किया गया था, तो उक्त अपराध के लिए उसे 1 से 5 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के मामले में, अधिनियम 2 से 10 वर्ष तक की कठोर सजा का प्रावधान करता है। इस कानून की समीक्षा भारत के संविधान के भाग-तीसरे में निहित मौलिक अधिकारों के अनुरूपता के संदर्भ में की जाएगी। यह अधिनियम दो व्यक्तियों के बीच विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन को भी कारावास से दंडनीय बनाता है, जो इस कानून से जुड़ा मुख्य विवाद का बिंदु है और वह प्रमुख आधार है।

याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए न्यायालय ने दंपतियों को धमकी मिलने की स्थिति में सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क करने की अनुमति दी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुलिस को उनकी उम्र और आरोपों की जांच करनी चाहिए और कानून के अनुसार सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करता है तो दंपतियों को शिकायत दर्ज कराने की स्वतंत्रता है। पसंद की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि विवाह वैध होने चाहिए। कुछ फैसलों में यह स्पष्ट किया गया है कि आर्य समाज मंदिरों में होने वाले विवाहों सहित सभी विवाहों को वैध होने के लिए कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना होगा और केवल प्रमाण पत्र ही आवश्यक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकते। यह स्पष्टीकरण अंतरधार्मिक दंपतियों को परेशान करने के लिए धर्मांतरण विरोधी प्रावधानों के दुरूपयोग को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि जबरन या धोखाधड़ी से किए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून का सख्ती से पालन किया जाए। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरधार्मिक संबंधों को गैरकानूनी धर्मांतरण से स्पष्ट रूप से अलग करता है। यह फैसला इस बात पर बल देता है कि वयस्क व्यक्तियों को अपने साथी चुनने और साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है।

अनसुनी 'ना'

मनीषा मंजरी

लेखक साहित्यकार हैं।

डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा का अधूरा सच

किसी भी स्वस्थ समाज की नींव आपसी सम्मान और व्यक्तिगत सीमाओं के प्रति संवेदनशीलता पर टिकी होती है। लेकिन जब एक महिला का 'मौन' भी 'संकेत' समझ लिया जाए, या उसकी स्पष्ट अस्वीकृति को 'चुनौती' के रूप में देखा जाए, तो यह केवल एक व्यक्तिगत असुविधा नहीं रह जाती, यह सामाजिक असंतुलन का संकेत बन जाती है। 'ना' एक सरल शब्द है, लेकिन इसके भीतर गहरा अर्थ छिपा है। यह किसी भी व्यक्ति की स्वायत्तता, उसकी पसंद और उसकी गरिमा का प्रतीक है। जब कोई महिला 'ना' कहती है, चाहे वह सीधे शब्दों में हो या उसके व्यवहार में, तो वह अपने अधिकार का प्रयोग कर रही होती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस 'ना' को स्वीकार करने के बजाय उसे नजरअंदाज किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यह अनदेखी अक्सर बार-बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने, लगातार संदेश करने या किसी प्रतिक्रिया के अभाव को 'रूचि' समझने के रूप में सामने आती है। यह व्यवहार केवल असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि एक प्रकार का डिजिटल अतिक्रमण है, जहाँ किसी की निजी सीमाओं को बार-बार भेदा जाता है, बिना उसकी अनुमति के। इस समस्या का समाधान बहुआयामी होना चाहिए। सबसे पहले, सहमति और व्यक्तिगत सीमाओं की समझ को प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा बनाना होगा। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि किसी की अस्वीकृति को स्वीकार करना ही वास्तविक सम्मान है। दूसरे, सामाजिक माध्यम संचालित करने वाली संस्थाओं को उत्पीड़न के मामलों में और अधिक सख्ती और पारदर्शिता दिखानी होगी। केवल शिकायत का विकल्प देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई भी जरूरी है। तीसरे, समाज के स्तर पर यह समझ विकसित करनी होगी कि, किसी की चुप्पी या दूरी, उसकी स्पष्ट इच्छा का संकेत है, और उसका सम्मान किया जाना चाहिए।

असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि एक प्रकार का डिजिटल अतिक्रमण है, जहाँ किसी की निजी सीमाओं को बार-बार भेदा जाता है, बिना उसकी अनुमति के।

डिजिटल क्रांति ने समाज को अभूतपूर्व गति दी है। संवाद, अभिव्यक्ति और अवसरों के नए द्वार खुले हैं। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी पहचान गढ़ने और अपनी बात दुनिया तक पहुँचाने का मंच दिया है। लेकिन इस चमकदार सतह के नीचे एक असहज सच्चाई अब भी मौजूद है, महिलाओं की 'ना' आज भी अनसुनी रह जाती है। यह समस्या नई नहीं है, लेकिन डिजिटल माध्यमों ने इसे एक नया स्वरूप दे दिया है। पहले जो असहजता सीमित दायरों में थी, अब वह बिना किसी भौतिक दूरी के, सीधे एक स्क्रीन के माध्यम से हमारे निजी जीवन में प्रवेश कर जाती है। अनचाहे संदेश, बार-बार फ्रेंड रिक्वेस्ट, और लगातार संपर्क करने की कोशिश। ये सब महज तकनीकी व्यवहार नहीं हैं, बल्कि उस मानसिकता का प्रतिबिंब हैं जहाँ सहमति को अब भी गंभीरता से नहीं लिया जाता।

किसी भी स्वस्थ समाज की नींव आपसी सम्मान और व्यक्तिगत सीमाओं के प्रति संवेदनशीलता पर टिकी होती है। लेकिन जब एक महिला का 'मौन' भी 'संकेत' समझ लिया जाए, या उसकी स्पष्ट अस्वीकृति को 'चुनौती' के रूप में देखा जाए, तो यह केवल एक व्यक्तिगत असुविधा नहीं रह जाती, यह सामाजिक असंतुलन का संकेत बन जाती है। 'ना' एक सरल शब्द है, लेकिन इसके भीतर गहरा अर्थ छिपा है। यह किसी भी व्यक्ति की स्वायत्तता, उसकी पसंद और उसकी गरिमा का प्रतीक है। जब कोई महिला 'ना' कहती है, चाहे वह सीधे शब्दों में हो या उसके व्यवहार में, तो वह अपने अधिकार का प्रयोग कर रही होती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस 'ना' को स्वीकार करने के बजाय उसे नजरअंदाज किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यह अनदेखी अक्सर बार-बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने, लगातार संदेश करने या किसी प्रतिक्रिया के अभाव को 'रूचि' समझने के रूप में सामने आती है। यह व्यवहार केवल असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि एक प्रकार का डिजिटल अतिक्रमण है, जहाँ किसी की निजी सीमाओं को बार-बार भेदा जाता है, बिना उसकी अनुमति के।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि इंटरनेट एक खुला मंच है, जहाँ किसी से भी संपर्क किया जा सकता है। यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन यह तर्क उस बिंदु पर असफल हो जाता है जहाँ संपर्क की कोशिश एकतरफा और ज़िद्दी हो जाती है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समस्या तकनीक में नहीं है। इंटरनेट केवल एक माध्यम है, समस्या उस सोच में है जहाँ, 'ना' को अंतिम उत्तर नहीं माना जाता, 'मौन' को सहमति का रूप दे दिया जाता है, और 'सम्मान' केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी तकनीकी समाधान अधूरा ही रहेगा।

हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ एक ओर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात जोर-शोर से की जाती है, वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक स्तर पर उनकी सीमाओं का लगातार उल्लंघन होता है। विज्ञापन, अभियानों और सार्वजनिक विमर्श में 'महिला सम्मान' को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार में वही सम्मान अक्सर अनुपस्थित होता है। यह विरोधाभास केवल शब्दों और कर्मों के बीच का अंतर नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक समस्या की ओर संकेत करता है। यह प्रश्न उठाना आवश्यक है कि, क्या हम वास्तव में महिलाओं की 'ना' को सुनने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सुरक्षा के कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं, ब्लॉकिंग, रिपोर्ट, प्राइवेसी सेटिंग्स आदि। लेकिन इन विकल्पों का होना ही पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को आज भी बार-बार इन टूल्स का सहारा लेना पड़ता है, जो यह दर्शाता है कि समस्या की जड़ कहीं और है। जब किसी को बार-बार ब्लॉक करना पड़े, तो यह केवल एक व्यक्तिगत समाधान है, सामाजिक नहीं। इसके अलावा, कई बार महिलाएँ रिपोर्ट करने या प्रतिक्रिया देने से हिचकिचाती हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि कहीं उन्हें ही सवालों के घेरे में न खड़ा कर दिया जाए। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि डिजिटल सुरक्षा का ढाँचा अभी भी अधूरा है, और इसे केवल तकनीकी उपायों से नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता से मजबूत किया जा सकता है।

इस समस्या का समाधान बहुआयामी होना चाहिए। सबसे पहले, सहमति और व्यक्तिगत सीमाओं की समझ को प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा बनाना होगा। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि किसी की अस्वीकृति को स्वीकार करना ही वास्तविक सम्मान है। दूसरे, सामाजिक माध्यम संचालित करने वाली संस्थाओं को उत्पीड़न के मामलों में और अधिक सख्ती और पारदर्शिता दिखानी होगी। केवल शिकायत का विकल्प देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई भी जरूरी है। तीसरे, समाज के स्तर पर यह समझ विकसित करनी होगी कि, किसी की चुप्पी या दूरी, उसकी स्पष्ट इच्छा का संकेत है, और उसका सम्मान किया जाना चाहिए।

डिजिटल युग ने हमें अभूतपूर्व अवसर दिए हैं, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियाँ भी आई हैं। यदि हम एक सुरक्षित और सम्मानजनक ऑनलाइन वातावरण बनाना चाहते हैं, तो हमें केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि अपनी सोच पर भी काम करना होगा। हर बार जब एक महिला की 'ना' को नजरअंदाज किया जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति की असुविधा नहीं होती, यह समाज के उस हिस्से को उजागर करता है जो अब भी सहमति और सम्मान की मूलभूत अवधारणा को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। अब समय आ गया है कि हम इस 'ना' को केवल सुनें ही नहीं, बल्कि उसे स्वीकार भी करें। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज की पहचान यही है कि वह अपने सबसे सरल और स्पष्ट संदेशों को भी गंभीरता से लेता है।

जीवन चर्या

अभिषेक झरबड़े

लाइफ मैनेजमेंट गुरु आश्रम व्यवस्था और पाठ्यक्रम पुरुषार्थ

स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि युवा वर्ग ही राष्ट्र के विकास का आधार है। ब्रह्मचर्य आश्रम, युवाओं के समग्र विकास की आधारशिला है। आज के समय में क्या वनों में गुरुकुल जाकर निवास करना पड़ेगा? तो मेरा उत्तर है ना। प्राचीन व्यवस्था तत्कालीन समाज की मांग थी। वर्तमान में छात्र वर्ग को केवल शिक्षा ही ग्रहण नहीं करनी बल्कि इस आश्रम में अनेकों कार्य सीखने हूँ। जैसे छात्र का चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास करना जो वर्तमान छात्रों में नहीं के बराबर है। हमारी व्यवस्था में शिक्षा के साथ सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य चारित्र निर्माण व व्यक्तित्व विकास ही है। मौजूदा सामाजिक परिदृश्य में अनुशासन, संयम स्वयं से ऊपर सर्व की भावना, निष्काम कर्म, विलासिता से दूरी, सहनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा जैसे चारित्रिक गुणों का विकास छात्रों में समय की मांग है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में निहित है। इसके साथ ही जैसे प्राचीन व्यवस्था में 64 कलाएँ सिखायी जाती थीं। वैसे ही अन्य बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है।

छात्र का चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास करना जो वर्तमान छात्रों में नहीं के बराबर है। हमारी व्यवस्था में शिक्षा के साथ सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य चारित्र निर्माण व व्यक्तित्व विकास ही है। मौजूदा सामाजिक परिदृश्य में अनुशासन, संयम स्वयं से ऊपर सर्व की भावना, निष्काम कर्म, विलासिता से दूरी, सहनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा जैसे चारित्रिक गुणों का विकास छात्रों में समय की मांग है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में निहित है। इसके साथ ही जैसे प्राचीन व्यवस्था में 64 कलाएँ सिखायी जाती थीं। वैसे ही अन्य बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ताकि बच्चों में नई-नई स्किल (कौशल) का विकास हो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इन 64 कलाओं से प्रभावित होकर कक्षा 6 से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत स्किल सिखाने का प्रावधान निहित है। सामान्यतः छात्र जीवन में धर्म पुरुषार्थ (अच्छी बातों को धारण करना) का ज्ञान व गृहस्थ आश्रम के लिए अर्थ पुरुषार्थ की नींव रखी जाती है।'

उपभोक्तावादी संस्कृति में सर्वाधिक आवश्यकता किसी आश्रम की है तो वो गृहस्थ आश्रम ही है। आज व्यक्ति वर्क-लाइफ बैलेंस में संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। इस समस्या का समाधान भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही दिया। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति धर्म के अनुसार अर्थ व काम की पूर्ति करे तो

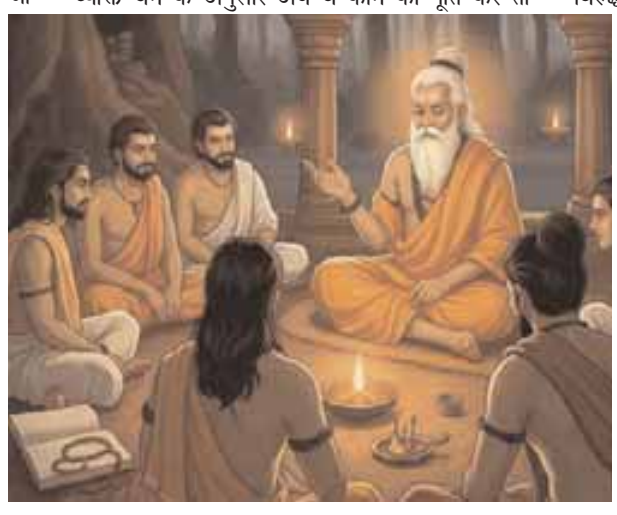

जीवन का संतुलन बना रहेगा और कभी अवसाद, तनाव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और जीवन का संतुलन बना रहेगा। अब एक सवाल आपके मन में उठ खड़ा होगा की कैसे धर्म के अनुसार अर्थ व काम की पूर्ति? तो उत्तर होगा की उदाहरण के समझें की कोई व्यक्ति अर्थ के लिए शिक्षा का पेशा चुनता है किंतु वह समय से स्कूल नहीं जाता, पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराता तो यह अनैतिक व धर्म के विरुद्ध काम होगा।अब काम की पुरुषार्थ की बात करें तो प्रश्न फिर उठता है की काम तो उपभोक्तावादी है? किंतु ऐसा नहीं है यह हमारी संकीर्ण सोच का नतीजा है । भारतीय जीवन दर्शन में 'काम' को एक पुरुषार्थ के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया ताकि गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों और आर्थिक संघर्षों के बीच मानवीय संवेदनाएं और जीवन का आनंद लुप्त न हो जाए। आज के युग में कला, मनोरंजन और भ्रमण इसके आधुनिक स्वरूप हैं। हालांकि, इन साधनों का उपयोग करते समय नैतिक शुचिता और धार्मिक मूल्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है, ताकि आनंद का मार्ग भटकाव का कारण न बने।

कई पश्चिमी विद्वान प्रश्न उठाते हैं कि ब्रह्मचर्य व गृहस्थ आश्रम की प्रासंगिकता तो कुछ सीमा तक दिखाई पड़ती है किंतु वानप्रस्थ व सन्यास आश्रम को ये लोग निराधार बताते हैं। वास्तव में इनके प्रश्न ही निराधार हैं क्योंकि दोनों आश्रमों की क्रियाएं आज भले ही प्रासंगिक न हों किंतु उनके उद्देश्य आज भी प्रासंगिक हैं। वानप्रस्थ की अवस्था रिटायरमेंट की स्थिति से है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है। इसे आज के समय एक उदाहरण रूप में समझें तो कोई शिक्षक रिटायरमेंट के बाद भी निःशुल्क कोचिंग या गाइडेंस दे तो यहाँ वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य चरितार्थ होता है।

वर्तमान में पश्चिमी देशों में मिनिमलिज्म का ट्रेंड चल रहा है। जिसमें कम साधनों में संतुष्ट रहने पर बल दिया जा रहा है। यही मॉडल हमारे संन्यास आश्रम की कॉपी है। जैसे - अहंकार, स्वार्थ से मुक्ति, डिजिटल डिटॉक्स होना, संपत्ति का समाज सेवा के लिए दान देना आदि।

भारतीय सनातन परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय–धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष–को किसी विशेष आश्रम या आयु की सीमा में नहीं बांधा जा सकता; इनकी प्राप्ति जीवन के हर सोपान पर संभव है। अनिवार्य केवल यह है कि इन सभी का आधार 'धर्म' हो। विडंबना यह है कि आधुनिक बोध में हमने धर्म को हिंदू, मुस्लिम या सिख जैसे सांप्रदायिक खानों में सीमित कर दिया है, जबकि वास्तव में धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं, बल्कि शाश्वत मानवीय मूल्य हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है- धैर्य, क्षमा, आत्म-संयम, अस्तेय (चोरी न करना), शुचिता, विवेक और सत्य का आचरण ही वास्तविक धर्म है। अंततः लेख का निष्कर्ष यह है की आश्रम व्यवस्था एक संपूर्ण जीवन का टाइम-टेबल भी है। अगर इस टाइम-टेबल का पालन हमने धर्म (नैतिकता) के आधार पर किया तो वर्तमान में समाज में विभिन्न समस्याएं जैसे - भ्रष्टाचार, तलाक, संस्कृति व समाज का दोहन, पर्यावरणीय असंतुलन का निदान इसी व्यवस्था में छिपा है।

आज की भागदौड़ भरी और भौतिकतावादी दुनिया में जब हम 'वर्क-लाइफ बैलेंस' और मानसिक शांति की खोज कर रहे हैं, तब हमारे ऋषियों द्वारा प्रतिपादित 'आश्रम व्यवस्था' एक संपूर्ण 'लाइफ मैनेजमेंट मॉडल' के रूप में उभरती है। प्रश्न यह है कि जब हमारे पास पहले से ही इतना वैज्ञानिक ढांचा मौजूद था, तो हमें बाहर समाधान खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

आश्रम व्यवस्था के मुख्यतः चार स्तंभ हैं- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व अंत में संन्यास आश्रम है। इन सभी के लिए 25-25 वर्षों का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन यह समय कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसमें उद्देश्य प्राप्ति हेतु परिवर्तन संभव है। जैसे- जगतगुरु शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। इस आश्रम व्यवस्था को चरितार्थ करने से पहले हमें पुरुषार्थ को समझने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है 'लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना'। अब प्रश्न आएगा की लक्ष्य क्या हैं? तो हमारे मनीषियों ने जीवन के कुल चार लक्ष्य बताए हैं। 'धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष'। पुरुषार्थ व आश्रम व्यवस्था में गहन संबंध है। सामान्य शब्दों में जानें तो पुरुषार्थ हमारे जीवन का पाठ्यक्रम है व आश्रम व्यवस्था इस सिलेबस को पूरा करने के लिए बनाया गया टाइम-टेबल है।'

स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि युवा वर्ग ही राष्ट्र के विकास का आधार है। ब्रह्मचर्य आश्रम, युवाओं के समग्र विकास की आधारशिला है। आज के समय में क्या वनों में गुरुकुल जाकर निवास करना पड़ेगा? तो मेरा उत्तर है ना। प्राचीन व्यवस्था तत्कालीन समाज की मांग थी। वर्तमान में छात्र वर्ग को केवल शिक्षा ही ग्रहण नहीं करनी बल्कि इस आश्रम में अनेकों कार्य सीखने हूँ। जैसे छात्र का चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास करना जो वर्तमान छात्रों में नहीं के बराबर है। हमारी व्यवस्था में शिक्षा के साथ सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य चारित्र निर्माण व व्यक्तित्व विकास ही है। मौजूदा सामाजिक परिदृश्य में अनुशासन, संयम स्वयं से ऊपर सर्व की भावना, निष्काम कर्म, विलासिता से दूरी, सहनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा जैसे चारित्रिक गुणों का विकास छात्रों में समय की मांग है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में निहित है। इसके साथ ही जैसे प्राचीन व्यवस्था में 64 कलाएँ सिखायी जाती थीं। वैसे ही अन्य बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ताकि बच्चों में नई-नई स्किल (कौशल) का विकास हो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इन 64 कलाओं से प्रभावित होकर कक्षा 6 से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत स्किल सिखाने का प्रावधान निहित है। सामान्यतः छात्र जीवन में धर्म पुरुषार्थ (अच्छी बातों को धारण करना) का ज्ञान व गृहस्थ आश्रम के लिए अर्थ पुरुषार्थ की नींव रखी जाती है।'

उपभोक्तावादी संस्कृति में सर्वाधिक आवश्यकता किसी आश्रम की है तो वो गृहस्थ आश्रम ही है। आज व्यक्ति वर्क-लाइफ बैलेंस में संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। इस समस्या का समाधान भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही दिया। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति धर्म के अनुसार अर्थ व काम की पूर्ति करे तो

जीवन का संतुलन बना रहेगा और कभी अवसाद, तनाव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और जीवन का संतुलन बना रहेगा। अब एक सवाल आपके मन में उठ खड़ा होगा की कैसे धर्म के अनुसार अर्थ व काम की पूर्ति? तो उत्तर होगा की उदाहरण के समझें की कोई व्यक्ति अर्थ के लिए शिक्षा का पेशा चुनता है किंतु वह समय से स्कूल नहीं जाता, पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराता तो यह अनैतिक व धर्म के विरुद्ध काम होगा।अब काम की पुरुषार्थ की बात करें तो प्रश्न फिर उठता है की काम तो उपभोक्तावादी है? किंतु ऐसा नहीं है यह हमारी संकीर्ण सोच का नतीजा है । भारतीय जीवन दर्शन में 'काम' को एक पुरुषार्थ के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया ताकि गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों और आर्थिक संघर्षों के बीच मानवीय संवेदनाएं और जीवन का आनंद लुप्त न हो जाए। आज के युग में कला, मनोरंजन और भ्रमण इसके आधुनिक स्वरूप हैं। हालांकि, इन साधनों का उपयोग करते समय नैतिक शुचिता और धार्मिक मूल्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है, ताकि आनंद का मार्ग भटकाव का कारण न बने।

कई पश्चिमी विद्वान प्रश्न उठाते हैं कि ब्रह्मचर्य व गृहस्थ आश्रम की प्रासंगिकता तो कुछ सीमा तक दिखाई पड़ती है किंतु वानप्रस्थ व सन्यास आश्रम को ये लोग निराधार बताते हैं। वास्तव में इनके प्रश्न ही निराधार हैं क्योंकि दोनों आश्रमों की क्रियाएं आज भले ही प्रासंगिक न हों किंतु उनके उद्देश्य आज भी प्रासंगिक हैं। वानप्रस्थ की अवस्था रिटायरमेंट की स्थिति से है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है। इसे आज के समय एक उदाहरण रूप में समझें तो कोई शिक्षक रिटायरमेंट के बाद भी निःशुल्क कोचिंग या गाइडेंस दे तो यहाँ वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य चरितार्थ होता है।

वर्तमान में पश्चिमी देशों में मिनिमलिज्म का ट्रेंड चल रहा है। जिसमें कम साधनों में संतुष्ट रहने पर बल दिया जा रहा है। यही मॉडल हमारे संन्यास आश्रम की कॉपी है। जैसे - अहंकार, स्वार्थ से मुक्ति, डिजिटल डिटॉक्स होना, संपत्ति का समाज सेवा के लिए दान देना आदि।

भारतीय सनातन परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय–धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष–को किसी विशेष आश्रम या आयु की सीमा में नहीं बांधा जा सकता; इनकी प्राप्ति जीवन के हर सोपान पर संभव है। अनिवार्य केवल यह है कि इन सभी का आधार 'धर्म' हो। विडंबना यह है कि आधुनिक बोध में हमने धर्म को हिंदू, मुस्लिम या सिख जैसे सांप्रदायिक खानों में सीमित कर दिया है, जबकि वास्तव में धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं, बल्कि शाश्वत मानवीय मूल्य हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है- धैर्य, क्षमा, आत्म-संयम, अस्तेय (चोरी न करना), शुचिता, विवेक और सत्य का आचरण ही वास्तविक धर्म है। अंततः लेख का निष्कर्ष यह है की आश्रम व्यवस्था एक संपूर्ण जीवन का टाइम-टेबल भी है। अगर इस टाइम-टेबल का पालन हमने धर्म (नैतिकता) के आधार पर किया तो वर्तमान में समाज में विभिन्न समस्याएं जैसे - भ्रष्टाचार, तलाक, संस्कृति व समाज का दोहन, पर्यावरणीय असंतुलन का निदान इसी व्यवस्था में छिपा है।

'संकट मोचन समारोह' में आज से बहेगी संगीत की गंगा

103वां संकटमोचन संगीत समारोह-1

राजेन्द्र शर्मा
(लेखक संगीत समीक्षक और पूर्व शासकीय अधिकारी हैं)

भारतीय शास्त्रीय संगीत में भारत का अपनी तरह के इकलौते और सबसे विराट संकट मोचन संगीत समारोह के 103वें आयोजन का आगाज छह से 11 अप्रैल तक वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के उसी प्रांगण में होने जा रहा है, जहां 923 में इसका पहला आयोजन हुआ था। छह दिन तक सुरों की गंगा बहेगी, जिसका आनंद पाने के लिए देश और दुनिया के कोने से लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंच रहे हैं। एक तरफ ऐतिहासिक नगरी का लावण्य तो दूसरी तरफ पूरे छह रोज़ तक कलाकारों की रस वर्षा। इसके वैभव की ज़रा कल्पना करिए: गंगा किनारे की मनोरम दुनिया और काशी का पुरातन वैभव। उस पर उन कलाकारों को निःशुल्क सुनने मिलना - जो प्रथम श्रेणी के सितारा फ़नकार माने जाते हैं। वह भी पूरे छह दिनों तक। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर प्रांगण में प्रतिदिन रात्रि ठीक साढ़े सात बजे इसका शुभारम्भ होगा और हर रोज भोर तक सुरों की गंगा निर्बाध बहेगी।

संकट मोचन संगीत समारोह के आयोजन का अपना एक इतिहास है। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निकट स्थित संकट मोचन का ऐतिहासिक मंदिर है। इसमें रखी हनुमानजी की मूर्ति को बाबा संकटमोचन कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मूर्ति को कवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने हाथों से गढ़ा था। मंदिर बाद में विस्तृत होता गया। ऐसी भी मान्यता है कि 16 वीं शताब्दी में तुलसीदासजी ने रामचरितमानस का एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा यहीं रहकर लिखा था। 60 के दशक तक प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला संकट मोचक संगीत समारोह काशी के स्थानीय कलाकारों पर ही निर्भर था। संकट मोचन मंदिर के तत्कारलीन मंहत पंडित अमरनाथ मिश्र जो स्वकयं पखावज के सिद्ध कलाकार थे, सरोद वादक पंडित ज्योजतिन भट्टाचार्य, तबला वादक पंडित किशन महाराज एवं पंडित आशुतोष भट्टाचार्य की मंडली इस आयोजन की रुपरेखा तैयार करती, परन्तु वर्ष 66-67 के दौरान तत्कालीन महंत प्रोफेसर वीरभद्रजी ने इसे राष्ट्रीय स्वरुप प्रदान करने की मंशा से पंडित मणिलाल जी (पंडित जसराज जी के बड़े भाई) को आमंत्रित किया। माना जाता है कि हनुमत कृपा से पंडित घराने के तीनों भाई मणिराम जी, प्रतापजी और जसराजजी देश के दिग्गज शास्त्रीय गायकों की श्रेणी में जा बैठे।

लम्बे वक़्त तक संकट मोचन संगीत समारोह में मुस्लिम और महिला कलाकारों की भागीदारी नहीं थी।

लेकिन तत्कालीन मंहत वीरभद्र मिश्र ने लिंग और मजहब की सीमा से परे इन कलाकारों को भी प्रस्तुति का अवसर दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ान ने यहां शहनाई बजाकर अपनी हाजिरी लगायी थी। यहां सभी को संगीत से मतलब है ।

वर्तमान में समारोह की ज़िम्मेदारी सम्हाल रहे मंहत विश्वंभरनाथ मिश्र ने इस समारोह को शास्त्रीय, जैज़, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए भी खोल दिया। इस की शुरुआत पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली ने की थी। हांलाकि उस समय शास्त्रीकय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र ने इसका विरोध किया था, लेकिन उसे किसी ने तवज्जो नहीं दी। मंहत विश्वंभर नाथ मिश्र कहते हैं कि संकट मोचन संगीत समारोह का प्रारूप संगीत और संस्कृति की पूरी अवधारणा को धार्मिक होने से बचाता है। संगीत समारोह और गंगा में एकरूपता है। जैसे गंगा सभी के लिए हैं, वैसे ही संकट मोचन का मंच भी सभी के लिए है। गंगा-जमुनी तहजीब और सौहार्द्र के लिए ख्यात संकट मोचन संगीत समारोह की मंशा को स्पष्ट करते हुए महंत विश्वंभर नाथ मिश्र गोस्वामी तुलसीदास को उद्धृत कर कहते हैं कि 'मांग के खइबो मसीद में सोइबो, लेइबो को एक न देइबो को दो' (मांग के खा लेंगे और मस्जिद में सो लेंगे, न किसी से कुछ लेना है और न किसी को कुछ देना है)। जब मुग़ल काल का यह हिंदी का महान कवि यह कह गया है, तो हमारी क्या मजाल कि हम उस समरूपता के साथ खिलवाड़ करें या किसी और को भी करने दें।

वर्ष 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय इंदिरा गांधी कमलापति त्रिपाठी से क़रीबी के चलते अक्सर बनारस आती रहती थीं। उस साल संकट मोचन संगीत समारोह में इंदिराजी अचानक पंहुच गईं। उस समय मंच पर कंकणा बनर्जी का गायन चल रहा था। सभी श्रोता कंकणा के सुरों में लीन । ऐसे में तत्कोलीन महंत प्रो. वीरभद्र मिश्र की यह दुविधा थी कि इंदिरा गांधी को कहां बिठाएं। महंतजी ने उन्हें मंच पर ही बिठा दिया। फिर भी श्रोता अपनी जगह से नहीं हिला और कंकणा ने अपना गायन पूरा किया ।

वाराणसी से सांसद और प्रधानमंत्री नरेन्द्रग मोदी अभी तक इस समारोह में चाहते हुए भी सम्मिलित नही हो सके हैं। यह कसक उनके दिल में भी है। पिछले वर्ष दो-दो मिनट के अंतराल पर प्रधानमंत्री ने पांच ट्वीट करते हुए लिखा था कि संकट मोचन संगीत समारोह संगीत प्रेमियों के लिए सौगात है। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के मन में भी यह मलाल है कि अभी तक वह इस संगीत समारोह में नही जा सके हैं।

संगीत मार्तंड पंडित जसराज ने एक बार कहा था कि पैसा, पारिश्रमिक और पद अपनी जगह है। लेकिन संकट मोचन संगीत समारोह में प्रस्तुति का जो आनंद है वह सारे आकर्षणों से परे है। पाकिस्तान के दिग्गज गजल गायक - गुलाम अली भी जिस दौर में यहां परफॉर्म करने आए वे स्वयं चकित थे! उनको इस प्रांगण में सुनना अपने आप में गौरवमयी पल था। इस समारोह में सुगम संगीत को भी मान्यता है। शास्त्रीय संगीत में उत्तर भारतीय के साथ दक्षिण भारतीय विधाएँ भी जोड़ी गई हैं। फिलहाल शास्त्रीय संगीत के रसिकों के दिलों में रोमांच है और प्रतीक्षा है छह अप्रैल की शाम की।

ठंडे बस्ते में एमआरएफ सेंटर की योजना, दुर्गंध से लोग परेशान

पुराना कचरे का निपटान नहीं, 10 टन नए कचरे का लगा ढेर

एस. द्विवेदी

बैतूल। शहर के गौठाना स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा प्रबंधन की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पुराने कचरे का निपटान अब तक पूरा नहीं हुआ है और नये कचरे का ढेर लगते जा रहा है। प्रतिदिन आने वाले नए कचरे की प्रोसेसिंग भी नहीं हो रही है। जिससे ट्रेंचिंग ग्राउंड में नया और पुराना मिलाकर करीब 10 टन कचरे का ढेर लग गया है। इस कचरे को 10 दिनों में हटाने के लिए सीएमओ ने ठेकेदार को निर्देशित किया है। बता दे कि नगरपालिका शहर के 33 वार्डो से निकलने वाले कचरे को गौठाना स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में एकत्रित करती है। यहां कचरा जमा किये जाने से कचरे का ढेर लग गया है। लंबे समय से कचरा इकठ्ठा होने और सडऩे की वजह से तेज दुर्गंध उठते रहती है। गंदगी व कचरे के कारण रहवासी घर के दरवाजे लगा कर रखते हैं। लोगों का आरोप है कि नगरपालिका द्वारा कचरे से उठने वाली दुर्गंध को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास तक नहीं किये जा रहे है। जबकि यहां पर ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन डाल दी जाए तो काफी हद तक यह बदबू दूर हो जाएगी। किन्तु नपा यहां पर किसी तरह का छिडकाव नहीं कर रही है।

प्रतिदिन निकलता है 35 से 40 टन कचरा – नगरपालिका द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहित किया जाता है। एक अनुमान से शहर के 33 वार्डो से लगभग प्रतिदिन 35 से 40 टन कचरा निकल जाता है और इस कचरे को शहर के समीप स्थित गौठाना के ट्रेचिंग ग्राउंड में जमा किया जाता है। पहले आसपास ज्यादा मकान नहीं थे, लेकिन अब आबादी बढऩे के साथ-साथ मकानों का भी निर्माण हो गया है। ऐसे में हवा चलने पर ट्रेंचिंग ग्राउंड का कचरा उडक़र घरों तक पहुंच जाता है और लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। रहवासी बताते है कि कचरे की दुर्गंध के कारण लोगों को सांस लेने में भी परेशानी आती है। कचरे के कारण मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ रहा है। यहां दूर-दूर तक लोग कचरे की दुर्गंध से परेशान है।

नये कचरे की प्रोसेसिंग समय पर नहीं– ट्रेंचिंग ग्राउंड में पुराने कचरे के निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा बेलेस्टिक प्लांट और ट्रोमल मशीन के माध्यम से काम किया जा रहा है, लेकिन इसकी गति धीमी है। इसी के चलते नए कचरे की प्रोसेसिंग समय पर नहीं हो पा रही है। सबसे अधिक समस्या फ्रेश कचरे से हो रही है, जिससे आसपास के इलाकों में दुर्गंध फैल रही है। दुर्गंध के कारण स्थानीय रहवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। हालांकि नगरपालिका का दावा है कि सीमित संसाधनों के बावजूद फ्रेश कचरे की प्रोसेसिंग की जा रही है, लेकिन हकीकत इससे अलग नजर आ रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

एमआरएफ सेंटर अधर में लटका– शहर में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 1.77 करोड़ रुपए की लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर बनाने की योजना अधर में लटक गई है। इस योजना के तहत सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग कर वैज्ञानिक तरीके से रिसाइक्लिंग होनी थी। नगरपालिका द्वारा इसका ले-आउट भी तैयार किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते यह योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई। रहवासी ट्रेंचिंग ग्राउंड को आबादी क्षेत्र से बाहर करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसे लेकर आसपास के लोगों ने विरोध भी किया था। यहां तक कि ट्रेंचिंग ग्राउंड जाने वाले मार्ग पर कई बार चक्काजाम तक किया जा चुका है।

इनका कहना है –

पुराने कचरे का निष्पादन चल रहा है। पंद्रह से बीस दिनों में कचरे का ढेर खत्म हो जाएगा। फ्रेश कचरे को लेकर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। एमआरएफ प्लांट का काम भी शुरू नहीं हो सका है। इसलिए दिक्कतें बनी हुई हैं।

– पंकज धुर्वे, सब इंजीनियर
नगरपालिका बैतूल

महामहिम ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन को बनाया मिशन, हृदयप्रदेश देश को दे रहा संदेश

राज्यपाल मंगुभाई पटेल के संवेदनशील प्रयासों से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन बन रहा जन-आंदोलन

बदनावर से राजेश शर्मा

5 अप्रैल रविवार की तिथि बाबा बैजनाथ की पावन धरा बदनावर और धार जिले के लिए ऐतिहासिक और गौरवमयी पलों के रूप में अंकित हो गई। महामहिम राज्यपाल मंगुभाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में शहीद के संघर्ष और बलिदान की गाथा भावी पीढ़ियों को प्रेरित करे इसी पावन बेला में धार जिले के गौरव, अमर शहीद नायब सूबेदार रवींद्र सिंह राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया वही बाबा बैजनाथ की पावन धरा से महामहिम ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन को जन-आंदोलन बनाने की पहल कर संवेदना की मिसाल पेश की। संवेदनशील राज्यपाल मंगुभाई पटेल बीमारी की वेदना को समझते

हुए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए मिशन के रूप में प्रयासरत है। सिकल सेल एनीमिया बीमारी निवारण के लिए आज हृदयप्रदेश देश को संदेश दे रहा है।

राज्यपाल ने मेगा स्वास्थ्य शिविर में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन को एक जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल मंत्र को अपनाकर ही इस अनुवांशिक बीमारी को समाज से दूर किया जा सकता है।

राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में सिकल सेल के विरुद्ध अभियान को गति देते हुए अब तक कुल 1 करोड़ 31 लाख जांचें सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या मुख्य रूप से जनजातीय समुदायों में व्याप्त है, इसलिए समाज के हर वर्ग को इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाते हुए मरीजों के लिए डिजिटल कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा, जिससे उपचार में सुगमता होगी। इसके साथ ही, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने और मरीजों की सहायता करने हेतु 'सिकल सेल मित्र' तैयार किए जा रहे हैं, जो इस मिशन में सेतु का कार्य करेंगे। राज्यपाल ने अपील की कि सिकल सेल के प्रति किसी भी प्रकार की भ्रांति न पालें और केवल पंजीकृत चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार ही दवाइयों का नियमित सेवन करें। इस बीमारी को निरंतर उपचार और सही जानकारी के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है।

गरिमामयी उपस्थिति .....

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक नीना विक्रम वर्मा, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेढ़ा, नगर पालिका अध्यक्ष मीना शेखर यादव, पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, अन्य जनप्रतिनिधिगण, शहीद नरेंद्रसिंह राठौर के परिवार के सदस्य, जिला प्रशासन के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग का अमला और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

खास-खास

- सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन एक साझा जिम्मेदारी, 'सबका साथ-सबका विकास' से ही संभव होगा समाधान
- डिजिटल कार्ड से मिलेगी मरीजों को सुगम उपचार की सुविधा
- जागरूकता के लिए बनाए जा रहे हैं 'सिकल सेल मित्र'
- राज्यपाल द्वारा सिविल अस्पताल, बदनावर के नवीन भवन का लोकार्पण भी किया गया।
- राज्यपाल की उपस्थिति में जिला रेडक्रॉस और अरविंदो हॉस्पिटल के मध्य एमओयू संपन्न
- सिकल सेल एनीमिया जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में धार रेडक्रॉस ने पेश की मिसाल

व्हाट्सएप ग्रुप में फंसाकर निवेश के नाम पर लाखों की ठगी, अकाउंट किया ब्लॉक

शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर 46 लाख की साइबर ठगी

बैतूल। ऑनलाइन शेयर बाजार में निवेश के नाम पर साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें अज्ञात जालसाजों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शिकायतकर्ता से 46,07,649 (छियालीस लाख सात हजार छह सौ उनचास रुपये) की ठगी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने थाना बैतूल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मार्च 2026 के दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने स्वयं को न्यू बैरी केपिटल प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप एवं इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड से जुड़ा बताकर फेसबुक के माध्यम से संपर्क किया। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जोडक़र उसे शेयर बाजार में निवेश के लिए प्रलोभित किया गया। आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता को न्यू बैरी-882 एक्सीलेंस क्राईसल एवं आईएफएल प्रोफोशनल नामक फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड कराए गए। इसके पश्चात 4 फरवरी से 9 मार्च के मध्य विभिन्न किश्तों में कुल 46,07,649 की राशि निवेश की। जालसाजों द्वारा फर्जी ट्रेडिंग अकाउंट में 37,39,149 का लाभ प्रदर्शित किया गया, जिससे शिकायतकर्ता का विश्वास और बढ़ गया, किन्तु जब उसने राशि निकालने का प्रयास किया, तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। आरोपियों द्वारा राशि निकालने के नाम पर 1,40,000 की अतिरिक्त मांग की गई, जिससे शिकायतकर्ता को ठगी का एहसास हुआ। शिकायत के आधार पर थाना गंज बैतूल में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) एवं 319(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

फेसबुक पर दोस्ती कर दुष्कर्म, आर्मी जवान गिरफ्तार

अविवाहित बताकर फंसाया, 1 साल से था फरार

बैतूल। कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले एक आर्मी जवान को महाराष्ट्र के अमरावती जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी संदीप धुर्वे पिछले एक साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। उसने फेसबुक के जरिए महिला से दोस्ती की थी और खुद को अविवाहित बताकर संबंध बनाए। जिससे पीड़िता का एक बेटा भी है। पुलिस ने मुखबिर और साइबर सेल की मदद से आरोपी को अमरावती जिले के वरुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है और उसे बैतूल लाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने पिछले साल 22 अप्रैल को अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2021 में उसकी फेसबुक पर संदीप धुर्वे से पहचान हुई थी। संदीप ने खुद को अविवाहित बताकर उससे प्रेम संबंध बनाए और शादी का वादा किया। पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी उसे महाराष्ट्र के परतवाड़ा और बाद में उत्तर प्रदेश के मेरठ में किराए के मकान में रखता रहा। वहीं पीड़िता की डिलीवरी भी कराई गई। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। जांच में पता चला कि आरोपी पहले से ही विवाहित है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी संदीप (34) पिता मूलचंद धुर्वे (निवासी परतवाड़ा) के

खिलाफ धारा 376(2)(एन) और 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। उस समय आरोपी मेरठ के तोपखाना कैंट में पदस्थ था।

तबादला करवाकर दे रहा था चकमा, वरुड़ क्षेत्र से पकड़ाया– पुलिस के मुताबिक, आरोपी को अपने खिलाफ मामला दर्ज होने की जानकारी मिल गई थी। इसके बाद उसका तबादला मेरठ से मणिपुर के लीमाकोंग और फिर नागालैंड के जखामा पोस्ट पर हो गया। वह करीब एक साल तक छुट्टी पर घर नहीं आया और पुलिस को चकमा देता रहा। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ट्रेन से अपने घर परतवाड़ा आ रहा है। आरोपी ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए बस से आने की गलत जानकारी भी दी थी। कोतवाली पुलिस की विशेष टीम ने अमरावती जिले के वरुड़ क्षेत्र के पास दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

बैतूल। महिला के साथ शारीरिक संबंध (बलात्कार) करने वाले आरोपी को सारनी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरियादीया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी रोहित सूर्यवंशी निवासी पाथाखेडा द्वारा फरियादिया के बच्चों का पालन पोषण करने का लालच व शादी का झांसा देकर उसके साथ सन 2022 से लगातार शारीरिक संबंध बनाये और शादी करने से मना कर दिया। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी रोहित सूर्यवंशी के विरूद्ध अपराध 69 बीएनएस का पाया जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी रोहित पिता रामा सूर्यवंशी उम्र 31 साल निवासी जेरी चौक शोभापर पाथाखेडा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जिला जेल बैतूल भेजा गया। इस कार्रवाही में निरीक्षक जयपाल इनवाती, उप निरीक्षक प्रीति पालेवार, प्रधान आरक्षक श्रीराम उईके और आरक्षक राजेन्द्र सैनिक राजेश की सराहनीय भूमिका रही।

कोई भी प्रभावित किसान फसल सर्वे में न छूटे, क्षति की रिपोर्ट बीमा पोर्टल पर भी दर्ज कराएं

अपर कलेक्टर ने मुलताई के ओलावृष्टि प्रभावित ग्रामों का किया निरीक्षण

बैतूल। कलेक्टर बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में ओलावृष्टि एवं वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे राजस्व, कृषि, पंचायत एवं उद्यानिकी विभाग के संयुक्त दल द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को अपर कलेक्टर वंदना जाट ने मुलताई क्षेत्र के प्रभावित ग्रामों का दौरा कर फसल क्षति का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम मुलताई राजीव कहार, तहसीलदार संजय बैरिया, सहायक यंत्री कृषि डॉ. प्रमोद मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर श्रीमती जाट ने ग्राम परमंडल, करपा एवं चंदौरा में किसानों के खेतों में पहुंचकर गेहूं, गोभी, टमाटर एवं प्याज की फसलों में हुए नुकसान का

जायजा लिया। उन्होंने किसानों से संवाद कर आश्वस्त किया कि कोई भी प्रभावित किसान सर्वे से नहीं छूटेगा। राजस्व, कृषि एवं पंचायत विभाग के दल द्वारा व्यवस्थित सर्वे कर फसल क्षति राहत की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों से अपील की कि वे अपनी फसल क्षति की सूचना बीमा कंपनी के निर्धारित नंबर एवं पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।

कृषक फसल क्षति की सूचना दें– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बैतूल जिले के जिन किसानों की फसल जलभराव या अतिवृष्टि से प्रभावित हुई है, वे अपनी फसल क्षति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 14447, व्हाट्सएप चैटबोट नंबर 7065514447 अथवा क्रॉप इंश्योरेंस एप के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए किसान प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर लॉगिन करते हुए अपनी क्षति का विवरण दर्ज करें। यदि सूचना दर्ज करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसल क्षति की सूचना अनिवार्य रूप से 72 घंटे के भीतर दर्ज कराएं, ताकि समय पर राहत की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

जनगणना 2027 : फील्ड ट्रेनर्स का जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न

प्रतिभागियों ने घर-घर जाकर मोबाइल एप के माध्यम से 33 प्रश्नों के उत्तर किए संकलित

बैतूल (निप्र)। जिले में जनगणना 2027 का प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 1 मई से 30 मई तक होगी। राष्ट्रव्यापी इस कार्य के सफल एवं त्रुटिरहित क्रियान्वयन के लिए जिले में फील्ड ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण एमएलबी स्कूल में शुक्रवार को संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी तथा अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती वंदना जाट के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि 64 फील्ड ट्रेनर्स के प्रथम वैच में 7 ग्रामीण चार्ज के 35 फील्ड ट्रेनर्स को दिनांक 24, 25 एवं 26 मार्च 2026 तथा द्वितीय बैच में 03 ग्रामीण चार्ज तथा समस्त 10 नगरीय चार्ज के कुल 29 फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 01, 02 एवं 03 अप्रैल 2026 को प्रतिदिन प्रातः 09:30 बजे से सायं 6 बजे तक पीएम श्री एमएलबी विद्यालय बैतूल में संपन्न हुआ। जिसमें जनगणना कार्य निदेशालय म.प्र. भोपाल से श्रीमती अनामिका जैन सहायक निदेशक एवं जिले के मास्टर ट्रेनर श्री विनोद कुमार अड़लक सहायक प्राध्यापक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के सक्रिय पर्यवेक्षण एवं परिणामोन्मुख दृष्टिकोण ने पूरे कार्यक्रम को एक सुदृढ़ दिशा प्रदान की, जिससे प्रशिक्षण पूरी तरह व्यवस्थित एवं प्रभावी रूप में संचालित हुआ।

प्रथम दिवस में जनगणना 2027 की रूपरेखा, प्रक्रियाएं एवं कानूनी प्रावधानों के साथ प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की भूमिका स्पष्ट की गई। द्वितीय दिवस में प्रश्नावली आधारित प्रशिक्षण के अंतर्गत मकान सूचीकरण से संबंधित प्रश्नों की गहन समझ विकसित कराई गई एवं मोबाइल एप के माध्यम से डेटा संकलन की प्रक्रिया का विस्तृत अभ्यास कराया गया। अंतिम दिवस में एप के सुरक्षा सावधानियों के साथ ही भूमिका निर्वहन मैप लेआउट निर्माण एवं फील्ड विजिट के माध्यम से प्रतिभागियों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करने का अनुभव प्रदान किया गया। जनपद बैतूल के ग्राम खंडारा में फील्ड अभ्यास के दौरान प्रतिभागियों ने घर-घर जाकर मोबाइल एप के माध्यम से 33 प्रश्नों के उत्तर संकलित करते हुए प्रगणक एवं पर्यवेक्षक की भूमिका का सफल निर्वहन किया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि जनगणना प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है और इसकी गुणवत्ता पर ही विकास योजनाओं की दिशा और प्रभावशीलता निर्भर करती है। प्रत्येक स्तर पर पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए कार्य को शत-प्रतिशत शुद्धता एवं समयबद्धता के साथ संपन्न किया जाना अनिवार्य है। फील्ड ट्रेनर्स इस पूरी प्रक्रिया की धुरी हैं, जिनकी दक्षता ही जनगणना की सफलता तय करेगी। उन्होंने फील्ड ट्रेनर्स को उनके दायित्वों की गंभीरता से अवगत कराते हुए स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता ही जमीनी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता तय करेगी, इसलिए प्रत्येक बिंदु को गहराई से समझते हुए आगे प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना की व्यापक उपयोगिता, डेटा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक सतर्कता एवं कार्य के प्रति संवेदनशीलता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विशेष बल दिया गया। त्रिदिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत प्रतिभागियों में डिजिटल माध्यम से जनगणना कार्य को सटीक, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संपन्न करने की आवश्यक दक्षता एवं आत्मविश्वास विकसित हुआ, जो जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उपार्जन से पहले गोदामों में गेहूं भंडारण के सत्यापन के लिए जांच दल गठित

सीहोर (निप्र)। शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन 10 अप्रैल से प्रारंभ होगा। रबी उपार्जन वर्ष अंतर्गत अन्य जिलों में खरीदी के लिए निर्धारित गोदामों पर खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व एवं बिना स्लॉट बुकिंग के गेहूं भंडारित करने का प्रकरण प्रकाश में आया है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री बालागुरू के. द्वारा जिले में गेहूं खरीदी के लिए निर्धारित गोदामों में इस वर्ष की खरीदी से पहले गेहूं के भण्डारण का भौतिक सत्यापन करने के लिए तहसीलवार एवं गोदामवार अधिकारियों के जांच दल गठित किए गए हैं। सभी अधिकारियों को गेहूं उपार्जन के लिए चिन्हांकित गोदामों की जांच कर 02 दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देश के पश्चात अधिकारियों के जांच दल गोदामों का निरीक्षण करने पहुंचे। जांच दलों द्वारा श्यामपुर स्थित जानकी वेयर हाउस, नीलेश वेयर हाउस कान्याखेड़ी स्थित पटेल वेयर हाउस, गिल्लोर स्थित सुदामा वेयरहाउस, बड़नगर स्थित कमला वेयरहाउस, प्रतीभा श्री वेयरहाउस, बोरदी कला स्थित श्री अष्ट विनायक वेयरहाउस, पांगरखाती स्थित कमला श्री वेयरहाउस, भंवरी कला महाकाल वेयर हाउस सहित जिले अनेक वेयरहाउसों का निरीक्षण किया गया।

संक्षिप्त समाचार

एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 26 साल पुराने घोटाले में पूर्व प्रबंधक गिरफ्तार, 1 करोड़ 86 लाख के गबन का है आरोप

भोपाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के तहत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 26 साल पुराने एक बड़े गबन मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। ब्यूरो ने 'सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल' के तत्कालीन प्रबंधक प्रदीप कुमार निखरा को गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई वर्ष 2000 में दर्ज अपराध क्रमांक 19/2000 के तहत की गई है।

उप मुख्यमंत्री ने किया पेंटियम प्वाइंट के तीन नवीन कॉलेजों का लोकार्पण

खो-खो खेल प्रतियोगिता के खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन

भोपाल। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने पेंटियम प्वाइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तीन नवीन महाविद्यालयों का भव्य लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में आयोजित अंतर-विश्वविद्यालयीन पश्चिम क्षेत्र खो-खो महिला प्रतियोगिता का निरीक्षण कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसके माध्यम से पेंटियम प्वाइंट कॉलेज

ऑफ फार्मेसी, पेंटियम प्वाइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट और पेंटियम प्वाइंट कॉलेज ऑफ लॉ का विधिवत संचालन शुरू हुआ। लोकार्पण के पश्चात श्री शुक्ल ने नवनिर्मित परिसर का भ्रमण किया और वहां उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं व सेमिनार हॉल का अवलोकन किया। उन्होंने संस्थान के मुख्य प्रबंध संचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सर्वसुविधायुक्त परिसर इस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा और उच्च शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। उप मुख्यमंत्री ने खो-खो प्रतियोगिता में भाग ले रही खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।

संस्कारयुक्त शिक्षा से ही मानव जाति का कल्याण व क्षेत्र का विकास संभव: उप मुख्यमंत्री

रजत जयंती समारोह संपन्न

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि संस्कारयुक्त शिक्षा से ही मानव जाति का कल्याण व क्षेत्र विकास संभव है। इस महाविद्यालय की स्थापना पवित्र उद्देश्य से की गई थी। महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करे व क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास में अपना योगदान दे। उप मुख्यमंत्री जवा में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जवा में इस महाविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा की पूर्ति की दिशा में बड़ा कदम था। जिसकी स्थापना के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी का योगदान अविस्मणीय रहेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि किसी भी संस्था का रजत जयंती समारोह उसकी यात्रा के सिंहावलोकन का भी एक माध्यम होता है। रीवा जिले में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और रीवा विकसित क्षेत्र में शामिल होने वाला है।

कलेक्टर ने की शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा

सीहोर, (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कक्षा पहली से कक्षा बारहवी तक के शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति की समीक्षा करते हुए नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक वितरण प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव ने भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त एचपीवी टीकाकरण की समीक्षा करते हुए जागरूकता कार्यक्रम चलाने और शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने वर्ष 2025-26 के लिए ई-स्कूल ड्रॉपआउट गैप का सत्यापन करने, विद्यार्थियों के आधार अपडेट की स्थिति सुधारने एवं शिक्षकों की उपस्थिति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने नवीन शौचालय निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया।

बैठक में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों को जारी आकस्मिक निधि के उपयोग की समीक्षा की गई तथा राशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि यू-डाइस 2025-26 अंतर्गत कक्षा 01 से 12 तक नामांकन का कार्य लगभग शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अब शेष छूटे हुए विद्यार्थियों को चिन्हित कर शीघ्र नामांकित किया जाए तथा ड्रॉपआउट की स्थिति को पूरी तरह समाप्त करने के प्रयास किए जाएं। बैठक में बताया गया कि शासन द्वारा जिले के सरकारी स्कूलों के 210 प्रतिभावन बच्चों को स्कूटी की राशि दी गई है तथा उनके द्वारा स्कूटी खरीद ली गई है।

फिश फीड मील से सफलता की उड़ान, मुस्कान सिंह और बनवारी लाल बने प्रगतिशील किसान

सीहोर (निप्र)। केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश में मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि करना, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आय बढ़ाना तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन, प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, फिश फीड यूनिट जैसी गतिविधियों के लिए ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सकें। इसी योजना ने सीहोर जिले की ग्राम हसनाबाद निवासी महिला किसान श्रीमती मुस्कान सिंह के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर न केवल स्वयं को सशक्त बनाया, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्रीमती मुस्कान सिंह बताती हैं कि उन्हें वर्ष 2025 के अप्रैल माह में इस योजना के अंतर्गत 01 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस राशि से उन्होंने एक आधुनिक फिश फीड मील की स्थापना की, जहां मछलियों के लिए उच्च गुणवत्ता का दाना तैयार किया जाता है।

इस कार्य में उनके पति श्री बनवारी लाल वर्मा भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। आज उनकी इस फिश फीड मील का वार्षिक टर्नओवर लगभग 05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो उनकी मेहनत और योजना की सार्थकता का प्रमाण है। इतना ही नहीं, इस इकाई के माध्यम से 14 लोगों को स्थायी रोजगार भी मिला है, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। श्रीमती मुस्कान सिंह द्वारा तैयार किया गया फिश फीड सीहोर जिले के साथ-साथ आसपास के लगभग 06 जिलों में विक्रय किया जा रहा है, जिससे उनका व्यवसाय लगातार विस्तार कर रहा है। आज वे और उनके पति एक प्रगतिशील किसान और सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। यह सफलता की कहानी दर्शाती है कि यदि योजनाओं का सही तरीके से लाभ लिया जाए तो वे न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव ला सकती हैं, बल्कि समाज और क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी प्रकार किसानों और उद्यमियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है।

भूरिया राजपूत बनीं सेल्स मैनेजर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया कदम

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से मिली सफलता

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर कु. भूरिया राजपूत ने रोजगार हासिल कर सफलता की प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत की है। उन्होंने लटेरी स्थित गणेश मोटर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ञ्ड्ड्स्ब्ह्ल्श्ह्ष्श्ह्ष्ठ्4 के शोरूम में सेल्स मैनेजर के पद पर नौकरी प्राप्त की है। कु. भूरिया राजपूत ने वर्ष 2025 में शासकीय महाविद्यालय लटेरी से कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उन्हें गणेश मोटर्स, लटेरी में अपने कौशल के अनुरूप कार्य करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने तकनीकी और व्यावसायिक अनुभव हासिल किया। उनकी लगन

और मेहनत के परिणामस्वरूप उनका चयन लटेरी के टीवीएस शोरूम में सेल्स मैनेजर के पद पर हुआ, जहां वर्तमान में उन्हें प्रतिमाह 8,000 रुपये वेतन प्राप्त हो रहा है। इस आय से वे न केवल अपने व्यक्तिगत खर्चों का वहन कर रही हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक सहायता भी कर रही हैं। भूरिया राजपूत ने अपनी सफलता का श्रेय शासकीय महाविद्यालय लटेरी एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश को दिया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त मार्गदर्शन और व्यावहारिक ज्ञान ने उन्हें रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सफलता अन्य युवाओं, विशेषकर युवतियों के लिए प्रेरणास्त्रोत है, जो कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने का यह प्रयास प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत केसला में जल संरक्षण का संदेश

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देश अनुसार जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद नर्मदा पुरम द्वारा जिले में विभिन्न गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। केसला में ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों द्वारा दीवार लेखन के माध्यम से जल संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है।

57 बालिकाओं को लगाई गई एचपीवी की वैक्सीन

सीहोर, (निप्र)। शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। सीएमएचओ डॉ सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि सीहोर जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में भी एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को एचपीवी की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी क्रम में 02 अप्रैल को जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में जिले की 57 बालिकाओं को एचपीवी की वैक्सीन लगाई गई।

सीएमएचओ डॉ सुधीर डेहरिया ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे जानलेवा कैंसर है। इस गंभीर बीमारी की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह राष्ट्रव्यापी एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान आगामी तीन माह तक पूरे देश में संचालित किया जाएगा।

नरवाई प्रबंधन में किसान अतुल अहिरवार बने मिसाल, भूसा बनाकर खेतों में मिला रहे अवशेष

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले के ग्राम छीरखेड़ा में प्रगतिशील कृषक श्री अतुल अहिरवार द्वारा नरवाई प्रबंधन को लेकर एक सराहनीय पहल की जा रही है। जहां आमतौर पर फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने की प्रवृत्ति देखी जाती है, वहीं कृषक श्री अहिरवार पर्यावरण संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और उपयोगी तरीका अपना रहे हैं। कृषक श्री अतुल अहिरवार हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई के बाद अपने खेत में नरवाई को जलाने के बजाय उसका भूसा तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही वे आसपास के गांवों के अन्य किसानों के खेतों में भी किराए पर जाकर भूसा बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के अन्य कृषकों को भी इस नवाचार का लाभ मिल रहा है। भूसा तैयार करने के बाद वे रोटावेटर चलाकर नरवाई को भूमि में मिला देते हैं। इससे खेत की उर्वरता में वृद्धि होती है, जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है और आगामी फसल के लिए भूमि अधिक उपजाऊ बनती है। यह तरीका न केवल पर्यावरण के लिए हितकारी है, बल्कि किसानों के लिए आर्थिक रूप से भी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। स्थानीय स्तर पर श्री अहिरवार की यह पहल अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है। यदि अधिक से अधिक किसान इस पद्धति को अपनाएं, तो नरवाई जलाने से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ-साथ मृदा संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है।

स्ट्रॉ रीपर से बदली तस्वीर: स्व सहायता समूह बना आत्मनिर्भर

नरवाई प्रबंधन से बढ़ी आय और बचा पर्यावरण

विदिशा (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास अब जमीनी स्तर पर सफल होते नजर आ रहे हैं। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में जिले के 22 स्व सहायता समूहों ने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आर्थिक स्वावलंबन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया है।

इन समूहों की महिलाओं द्वारा 22 स्ट्रॉ रीपर मशीनों का सफल संचालन किया जा रहा है। जिन समूहों के पास पहले से ट्रैक्टर-ट्रॉली उपलब्ध थे, उन्होंने संकुल स्तरीय संगठनों एवं बैंकों से ऋण

लेकर स्ट्रॉ रीपर मशीनें खरीदीं और इसे स्वरोजगार का साधन बना लिया। इस पहल के माध्यम से गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बची पराली (नरवाई) को जलाने के बजाय उसे भूसे में परिवर्तित किया जा रहा है।

अब तक इन मशीनों के जरिए लगभग 400 हितग्राहियों के खेतों में 840 ट्रॉली से अधिक भूसा तैयार किया जा चुका है, जिससे करीब 5 लाख,80 हजार रुपए की आय अर्जित हुई है। यह उपलब्धि न केवल समूहों की आर्थिक सशक्तता को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, कौशल और नेतृत्व क्षमता का भी प्रमाण है। इस नवाचार से जहां एक ओर नरवाई जलाने की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है, वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन के लिए भूसे की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे पशुपालकों को सीधा लाभ मिल रहा है। पहले जहां किसान पराली को बेकार समझकर जला देते थे, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता था, वहीं अब वही पराली आय का साधन बन गई है। आजीविका मिशन के तहत यह पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बन रही है और अन्य समूहों को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नरवाई प्रबंधन कार्यों की लगातार समीक्षा एवं मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिससे स्व सहायता समूह और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। यह पहल आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव की दिशा में एक सशक्त कदम है, जो 'आत्मनिर्भर गांव' की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आष्टा में स्टॉक सत्यापन में अनियमितता पाए जाने पर गैस एजेंसी से 05 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने और घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए आष्टा में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री मृगी अग्रवाल ने द्वारा आष्टा के विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट एवं गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान विपिन गैस एजेंसी पर स्टॉक सत्यापन में अनियमितताएं होने पर 05 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए गए और प्रकरण दर्ज किया गया।

मप्र से राजस्थान तक ओलों से तबाही!

14 जिलों में आसमान से बरसी 'सफेद आफत' नीबू से बड़े आकार के ओले गिरे

भोपाल (नप्र)। भीषण ओलावृष्टि, आंधी-तूफान और बारिश ने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कहर बरपा दिया। पिछले 24 घंटों में एमपी 14 जिलों में ओलों की बारिश हुई है। राजगढ़ में तो नींबू से बड़े आकार के ओले पड़े। मुलताई-बैतूल में करीब आधे घंटे में पूरा इलाका शिमला सा नजर आ रहा था। एमपी से लेकर पड़ोसी राजस्थान तक ओलों ने फसलें बर्बाद कर दी और लोगों का हाल-बेहाल कर दिया। सोमवार को 20 जिलों में बारिश-तूफान का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में मौसमी सिस्टम के कारण भयंकर तूफान और आंधी के साथ ओले और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। शनिवार को राजगढ़ जिले से लेकर राजस्थान के पड़ोसी जिले झालावाड़ तक ओलों ने कहर बरपा दिया। नींबू से बड़े आकार के लोगों से गरीब के घर उजड़ गए। खेतों में फसलें चौपट हो गई मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी प्रदेश के 20 जिलों में बारिश और तूफान का अलर्ट दिया है।

7 अप्रैल से नया सिस्टम होगा सक्रिय

मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में सक्रिय कई मौसम प्रणालियों के चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बादलों का डेरा रहेगा, वहीं 7 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में दस्तक देने वाला है, जिसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा।

मध्यप्रदेश पर क्या होगा असर?

नए मौसमी सिस्टम से पूर्वी मध्यप्रदेश जिसमें शहडोल, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर शामिल हैं। इन जिलों में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण आंशिक बादल छाए रहेंगे। शाम या रात के समय गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। पश्चिमी एवं उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र जिसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर शामिल हैं यहां मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि, हल्के बादल आ-जा सकते हैं, लेकिन गर्मी से विशेष राहत की उम्मीद फिलहाल कम है। हवाओं की रफ्तार की बात करें तो प्रदेश के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

7 अप्रैल 2026 से एक नया और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से पूरे मध्यप्रदेश में मौसम बदल सकता है, जिससे आंधी, बादल और बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के संकेत हैं मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के 14 जिलों में जोरदार ओलावृष्टि हुई है। सबसे ज्यादा ओले बैतूल और मुलताई में गिरे हैं। राजगढ़ जिले में पूरे इलाके में सबसे बड़े ओले गिरे हैं। यहां नीबू से बड़े 200 ग्राम तक के ओले आसमान से गिरे। वहीं मंदसौर, श्योपुरकलां, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, छतरपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, बैतूल, नरसिंहपुर जिले सहित अन्य इलाकों में ओलावृष्टि हुई है।

जिला कलेक्टर्स आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का त्वरित कराएं आकलन : मुख्यमंत्री

किसान भाइयों को तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी सहायता और राहत

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के संबंध में कहा है कि किसान भाई चिंता न करें, संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला कलेक्टर्स को मौसम के असमय बदलाव से हुए नुकसान का त्वरित आकलन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में हुई हानि के लिए तत्काल सहायता और राहत उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि गत दिवस ग्वालियर-चंबल संभाग के विभिन्न जिलों तथा राजगढ़, रायसेन, बैतूल आदि जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में गेहूं उपार्जन की तैयारियों के साथ खाद्य विभाग की समीक्षा की।

भारत का समय, पृथ्वी का समय

बाबा विश्वनाथ को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समर्पित की वैदिक घड़ी

वाराणसी। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भेंट की, जिसे बाबा विश्वनाथ के मंदिर प्रांगण में स्थापित किया गया। कालगणना के केन्द्र महाकाल की नगरी उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के स्थापना के बाद यह भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंगों में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की दूसरी स्थापना हैद्य उज्जैन में पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2024 में किया था। इस घड़ी को वैदिक काल गणना के समस्त घटकों को समवेत कर बनाया गया है। यह घड़ी सूर्योदय से परिचालित है। अतः जिस स्थान पर जो सूर्योदय का समय होगा उस स्थान की काल गणना तदनुसार होगी। स्टेंडर्ड टाइम भी उसी से जुड़ा रहेगा। इस घड़ी के माध्यम से वैदिक समय, लोकेशन, भारतीय स्टेंडर्ड टाइम, भारतीय पंचांग, विक्रम सम्वत् मास, ग्रह स्थिति, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति आदि की जानकारी समाहित है। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार डॉ. श्रीराम तिवारी ने बताया कि भारत ने विश्व को सूर्य और प्रकृति के अनुरूप समय-निर्धारण का अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया हैद्य वाराणसी के बाद अब आगामी समय में राम मंदिर सहित अभी ज्योतिर्लिंगों पर भी वैदिक घड़ी की स्थापना की जाएगी। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के माध्यम से प्रतिदिन के सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक गणना के साथ-साथ दिन के 30 मुहूर्तों का विस्तृत और प्रामाणिक विवरण प्राप्त होगा। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी आधुनिकता और परंपरा के समन्वय की एक सशक्त प्रतीक है। यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है, बल्कि युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देती है।

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, उज्जैन द्वारा भारतीय कालगणना पर आधारित विश्व की प्रथम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। यह घड़ी भारत की प्राचीन कालगणना परंपरा को आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से पुनर्स्थापित करने का एक अभिनव प्रयास है।

यह घड़ी सूर्य के कोण तथा पर्यवेक्षक की स्थान-विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को सम्मिलित कर समय का निर्धारण करती है। जिस स्थान पर सूर्योदय का समय होता है, उसी के अनुसार उस स्थान का वैदिक समय प्रदर्शित किया जाता है।

भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं : अजय जामवाल

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल ने रविवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के अंतर्गत देवास जिले की देवास विधानसभा के पांचों मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ सत्र को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विचार आधारित संगठन है। भाजपा का मूल उद्देश्य राष्ट्र सेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करता है और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने पंच निष्ठाएं और पंच परिवर्तन को कार्यकर्ता जीवन का आधार बताते हुए कहा कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इन सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। श्री अजय जामवाल ने इंदौर के निपानिया मंडल प्रशिक्षण वर्ग में रात्रि विश्राम कर रविवार सुबह कार्यकर्ताओं के साथ योग एवं प्राणायाम में सहभागिता की। उन्होंने रविवार को उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन-पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय ही सक्रिय नहीं रहते हैं, बल्कि वह समाज के हर क्षेत्र में सेवा और समर्पण के साथ कार्य करते हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की भावना के साथ कार्य करना ही भाजपा की पहचान है। इसी के माध्यम से कार्यकर्ता समाज में विश्वास और विश्वसनीयता स्थापित करता है। पंच निष्ठाएं जहां कार्यकर्ता के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करती हैं, वहीं पंच परिवर्तन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनते हैं।

सशक्त कार्यकर्ता ही सशक्त संगठन की नींव

भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल ने कहा कि भाजपा की पंच निष्ठाएं कार्यकर्ता के चरित्र और उसके कार्य की दिशा तय करती हैं। कार्यकर्ता के मन में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना होना अनिवार्य है, यही राष्ट्र निष्ठा का मूल है। पार्टी की विचारधारा के प्रति अटूट विश्वास रखना विचार निष्ठा का आधार है। संगठन के निर्णयों और अनुशासन का पूर्ण पालन करना संगठन निष्ठा को सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के व्यक्तिगत जीवन में शुचिता, ईमानदारी और नैतिकता का होना आवश्यक है, जो उसकी आचरण निष्ठा को दर्शाता है। समाज के अंतिम व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना सेवा निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पंच निष्ठाएं ही एक साधारण कार्यकर्ता को आदर्श कार्यकर्ता में परिवर्तित करती हैं और संगठन की मजबूती का आधार बनती हैं।

कोख से बच्ची निकाली और पेट में छोड़ दिया सर्जिकल नैपकिन!

खरगोन में गायनोकॉलोजिस्ट की जानलेवा लापरवाही

खरगोन (नप्र)। जरा सोचिये सीजेरियन प्रसव के दौरान महिला की कोख से बच्ची तो सुरक्षित निकाली ली जाए, लेकिन पेट में सर्जिकल नैपकिन अंदर ही छोड़कर पेट वापस सिल दिया जाए तो क्या होगा? एमपी के खरगोन जिला अस्पताल में गायनिक टीम ने ऐसी ही जानलेवा लापरवाही कर दी। एक महिला की जान खतरे में डाल दी। बेतहाशा दर्द से तड़पती महिला का इंदौर में दोबारा ऑपरेशन कर पेट से नैपकिन निकाली है।

मध्य प्रदेश के खरगोन जिला अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान एक महिला के पेट में कथित रूप से सर्जिकल नैपकिन छूट जाने के मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया कि इंदौर के जिस निजी अस्पताल ने परिवार को नैपकिन छूट जाने के बारे में जानकारी दी है, उससे इस संबंध में लिखित दस्तावेज मांगे गए हैं। मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है, जिसे तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

निजी अस्पताल पहुंचे तो खुलासा हुआ कि पेट में कुछ है

वहीं, महिला के पति विनोद ने बताया कि डिस्चार्ज के बाद उसकी पत्नी को पेट में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, जब हम उसे दोबारा जिला अस्पताल ले जा रहे थे, तब रास्ते में खरगोन के एक निजी सर्जन को दिखाया, जहां पेट में कुछ जमा होने की आशंका जताई गई और इंदौर जाने की सलाह दी गई। इसके बाद उसे जिला अस्पताल ना ले जाते हुए 30 मार्च को उसे इंदौर के एमटीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद एमवाय अस्पताल में ऑपरेशन की सलाह दी गई।

ऑपरेशन कर सर्जिकल नैपकिन निकाली गई

उन्होंने आगे बताया कि पत्नी की हालत बिगड़ने पर उसे इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 31 मार्च को ऑपरेशन के दौरान उसके पेट से सर्जिकल नैपकिन निकाली गई। परिवार ने यह भी बताया कि निजी अस्पतालों में इलाज के चलते उन्हें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसी बीच, कलेक्टर भव्या मित्तल ने शनिवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

ऑपरेशन से पहले और बाद में सभी उपकरण-सामग्री गिनती का नियम

जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ. राजकुमारी देवड़ा के अनुसार, भीकनगांव क्षेत्र के सेल्दा गांव निवासी 30 वर्षीय मनीषा घोरमाड़े को 16 मार्च को प्रसव पीड़ा के चलते भर्ती कराया गया था। 17 मार्च को सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए उसने एक बच्ची को जन्म दिया और 21 मार्च को उसे स्वस्थ हालत में छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार ऑपरेशन से पहले और बाद में सभी उपकरणों और सामग्री की गिनती की जाती है।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

क्या छत्तीसगढ़ में 2028 का चुनाव नए परिसीमन के साथ होगा?

पिछले माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2028 का विधानसभा चुनाव नए परिसीमन के आधार पर होगा। अभी नई जनगणना होनी है और 2027 तक जनगणना का काम पूरा होगा, पर अंतिम आंकड़े आने में समय लगेगा। संकेत हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर विधानसभा सीटों का निर्धारण होगा। छत्तीसगढ़ में अभी 90 विधानसभा सीटें हैं। कहा जा परिसीमन के बाद सीटें 135 तक पहुँच जाएगी। चर्चा है कि केंद्र सरकार 16 अप्रैल से दो-तीन दिन का संसद सत्र बुलवाकर इस बारे में फैसला लेने वाली है, इसके बाद स्थिति साफ़ होगी। कहा जा रहा है कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन की खबरों ने राजनीतिक दलों के नेताओं,मंत्री-विधायकों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है।

सुबोध सिंह मिड करियर ट्रेनिंग में जाएंगे

कहते हैं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह 6 से 24 अप्रैल तक मिड करियर ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाने वाले हैं। आमतौर पर 25 साल की सेवा के बाद मिड करियर ट्रेनिंग के लिए आईएएस अफसर लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी जाते हैं। कहा जा रहा है कि 1997 बैच के आईएएस सुबोध सिंह के मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम से लौटने के बाद ही आईएएस अफसरों के तबादले होंगे। उम्मीद की जा रही है कि मंत्रालय और जिला स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले मई के दूसरे हफ्ते में होंगे, तब तक पांच राज्यों की चुनाव ड्यूटी में गए आईएएस अफसर भी लौट कर आ जाएंगे। माना जा रहा है कि अबकी प्रशासनिक फेरबदल में मंत्रालय स्तर पर व्यापक बदलाव होंगे। कई सचिवों के प्रभार इधर से उधर होंगे। दो साल से अधिक समय से एक ही जिले में पदस्थ कलेक्टर भी प्रभावित हो सकते हैं।

मक्सी कुजूर बनेंगे इरिगेशन ईएनसी

कहते हैं मंत्रालय में जल संसाधन विभाग के ओएसडी मक्सी कुजूर विभाग के प्रभारी ईएनसी होंगे। मक्सी कुजूर संविदा पर चल रहे ईएनसी इंद्रजीत उइके का स्थान लेंगे। वरिष्ठता सूची में मक्सी कुजूर से ऊपर महानदी रीवर प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर शंकर ठाकुर हैं, पर शंकर ठाकुर दो महीने बाद रिटायर हो जाएंगे। इस कारण मक्सी कुजूर दौड़ में आगे चल रहे हैं। चीफ इंजीनियर मक्सी कुजूर करीब तीन साल तक ईएनसी रहेंगे। वैसे मक्सी कुजूर चर्चित अफसर हैं और कई मामलों में उलझ चुके हैं, पर विभाग में वरिष्ठ अफसरों की कमी का लाभ मक्सी कुजूर को मिलता दिख रहा है। बताते हैं मक्सी कुजूर जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश टोप्पो की पसंद हैं। मक्सी कुजूर की जगह मंत्रालय में जल संसाधन विभाग का ओएसडी आलोक अग्रवाल को बनाए जाने की खबर है। बताते हैं पोस्टिंग से पहले ही आलोक अग्रवाल का विरोध भी शुरू हो गया है। आलोक अग्रवाल का जल संसाधन विभाग के अधिकारी और ठेकेदार विरोध कर रहे हैं। सुना जा रहा है कि ईओडब्ल्यू की जाँच के चलते आलोक अग्रवाल का प्रमोशन लटका है। वे अभी कार्यपालन अभियंता ही हैं, जबकि उनसे कनिष्ठ अधीक्षण अभियंता प्रमोट हो गए हैं। अलोक अग्रवाल को डॉ रमन सिंह के राज में ईओडब्ल्यू द्वारा दबोचा गया था और भूपेश बघेल के राज में उनकी वापसी हो गई। विभाग के ठेकेदार और अफसर आलोक अग्रवाल को प्रोजेक्ट में पच्चड़ फ़साने वाले मानते हैं। हवा है कि मक्सी कुजूर और आलोक अग्रवाल दोनों ही एक ही ठेकेदार के शिकार हुए थे और अब दोनों नए मुकाम की दौड़ में हैं।

चुनाव और आफिस ड्यूटी साथ-साथ

कहते हैं पश्चिम बंगाल,तमिलनाडु,असम, केरल और पांडिचेरी चुनाव ड्यूटी में गए कुछ अफसर चुनाव आव्जर्वर के साथ आन लाइन फाइलें भी निपटा रहे हैं। बताते हैं सरकार ने अफसरों के छुट्टी या दूसरी ड्यूटी पर जाने की स्थिति में विभागीय कामकाज के निपटारे के लिए लिंक आफिसर की व्यवस्था की है, पर चुनाव ड्यूटी पर गए कुछ अफसर फाइलें आन लाइन ही बुलवा रहे हैं। लिंक ऑफिसर को फाइलें नहीं जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में ई फाइल सिस्टम के चलते विभाग से मोह पालने वाले अफसरों के लिए यह सुअवसर बन गया है। चर्चा है कि राज्य से बाहर रहते कुछ अफसरों ने जाते-जाते वित्तीय वर्ष की फ़ाइल धड़ल्ले से निपटाई। बताते हैं फाइलें उनकी नजर से गुजरने से हिसाब-किताब का अंदाजा भी रहा। दूसरे राज्य में रहते विभाग की फाइलें आन लाइन निपटाने को क्या माना जाय, इसे मातहत समझ नहीं पा रहे हैं। साहब राज्य सरकार की ड्यूटी पर हैं या फिर चुनाव आयोग की ड्यूटी पर। आमतौर पर माना जाता है कि चुनाव ड्यूटी में लगे अफसर चुनाव आयोग के अधीन रहते हैं। इस बार राज्य में नया ट्रेंड सुनने को मिला।

प्रभारी एसपी का बदला जाना चर्चा में

जांजगीर-चांपा जिले के एसपी विजय पांडे के ट्रेनिंग में जाने के कारण डीजीपी के आदेश पर दो अप्रैल को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 11 वीं वाहिनी जांजगीर-चांपा के सेनानी बिमल कुमार बैस को पहले प्रभारी एसपी बनाया गया था, पर उसी दिन आदेश बदल कर श्री बैस की जगह छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल छठवीं वाहिनी रायगढ़ की सेनानी निवेदिता पाल को जांजगीर-चांपा का प्रभारी एसपी बना दिया। अब डीजीपी साहब ने आदेश क्यों बदला चर्चा का विषय है। श्री बैस आईपीएस हैं और निवेदिता पाल अभी राज्य पुलिस सेवा की अफसर हैं। जांजगीर-चांपा जिले के एसपी विजय पांडे के अलावा रायपुर ग्रामीण की एसपी श्वेता श्रीवास्तव,कोंडागांव के एसपी पंकज चंद्रा और गरियाबंद के एसपी वेदव्रत सिरमौर 06 अप्रैल से 15 मई तक प्रशिक्षण के लिए सरदार वल्लभव भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 20 वीं वाहिनी महासमुंद की सेनानी मनीषा ठाकुर रावटे रायपुर ग्रामीण की प्रभारी एसपी होंगी। एसटीएफ बघेरा जिला-दुर्ग के एसपी त्रिलोक बंसल को कोंडागांव की जिम्मेदारी दी गई है। गरियाबंद की जिम्मेदारी नीरज चंद्राकर संभालेंगे। नीरज चंद्राकर अभी पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक एसआईए हैं।

जल्दी मिल सकता है पर्यावरण मंडल को अध्यक्ष

कहते हैं छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल के अध्यक्ष पद के लिए एक वरिष्ठ आईएफएस का नाम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अभी पर्यावरण सचिव के नाते अंकित आनंद छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल में अब तक पर्यावरण सचिव को ही अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा रही है। अब देखते हैं यह परंपरा बदलती है या फिर चलती रहती है। पर्यावरण मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी की पसंद मायने रखेगा। राज्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल महत्वपूर्ण संस्था है।

बैठक के साथ पूजा-पाठ भी

राज्य के प्रभारी डीजीपी अरुणदेव गौतम अपने सरगुजा-जशपुर दौरे में पुलिस अफसरों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ अंबिकापुर में महामाया की पूजा-अर्चना भी की। प्रभारी डीजी के रूप में एक साल से अधिक का समय गुजार चुके गौतम साहब स्थायी डीजीपी बनने की दौड़ में हैं। यूपीएससी के पैनल में नाम आने के बाद भी अरुणदेव गौतम को स्थायी डीजीपी बनने का मौका अब तक नहीं मिला है। राज्य में अब तक स्थायी डीजीपी नहीं बनाए जाने के मुद्दे पर अब यूपीएससी में पूछताछ की है , तो शायद फिर गौतम साहब की आस जगी है। अरुणदेव गौतम जुलाई 2027 में रिटायर होंगे, ऐसे में अभी उनका कार्यकाल एक साल से ज्यादा बचा है, पर स्थायी डीजीपी बन जाते हैं तो दो साल के पहले पद से नहीं हटाए जा सकेंगे।

शशि सिंह की अलग धारा

कहते हैं सूरजपुर जिला की कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह अलग लाइन खींचने में लगी हुई हैं। बताते हैं जिला कार्यकारिणी से टी एस सिंहदेव के कुछ समर्थकों के इस्तीफे बाद शशि सिंह ने धारा बदल दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सरगुजा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही शशि सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समर्थक माना जाता है। शशि सिंह के शपथ समारोह में भूपेश बघेल की मौजूदगी और टी एस सिंहदेव की गैर हाजिरी चर्चा में रही। माना जा रहा है कि न चाहते हुए भी सिंहदेव साहब शशि सिंह का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। एक तो सूरजपुर में उनके पास मजबूत टीम नहीं है और शशि सिंह टीम राहुल से जुडी हैं। शशि सिंह के तेवर को देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अब पूरे सरगुजा संभाग में टी एस सिंहदेव का दबदबा रहा नहीं।